राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 69 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,09 सितम्बर 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नजर...

आपात स्थिति में राजमार्ग पर उतरेंगे सेना के विमान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश में पहली बार वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतारने की तैयारी पूरी की गई है तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को राजस्थान के बाड़मेर में इसका उद्घाटन करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि श्री सिंह और श्री गडकरी बाड़मेर के दक्षिण में गांधव-बाखासर सेक्शन-राष्ट्रीय राजमार्ग-925 पर के लिए एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड-ईएलएफ का उद्घाटन करने के बाद वहां इस सुविधा का अवलोकन करेंगे।

अक्षय कुमार की मां अरुणा का निधन

मुंबई, (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का मुंबई में बुधवार को निधन हो गया है। अक्षय ने इसकी जानकारी खुद अक्षय ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि वह मेरी सब कुछ थीं, आज मैं बहुत दर्द में हूँ, ये दर्द असहनीय है। उन्होंने लिखा कि बुधवार सुबह मां का निधन हो गया। वह इस दुनिया को छोड़कर अब दूसरी दुनिया में पिता से फिर मिल गईं। मैं आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करता हूं। ओम शांति। वहीं, डायरेक्टर आनंद एल राय की मां का भी बुधवार सुबह निधन हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए अभिनेता अक्षय कुमार भी पहुंचे।

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी का इस्तीफा

देहरादून, (एजेंसी)। दो दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज होने लगी थीं। उन्हें उप्र बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की है। बेनी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने तीन साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुकी हैं। दो दिन पूर्व गृह मंत्री शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही उनके इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज होने लगी थीं। उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हैं।

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने इकबाल सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। लालपुरा अब तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे और अल्पसंख्यक सिख समुदाय से आते हैं। इससे पहले गैयुरूल हसन रिजवी आयोग के अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल पिछले साल मई में पूरा हो गया था। आयोग में फिलहाल एकमात्र सदस्य आतिफ रशीद हैं जो उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

एक्टर राणा दग्गुबाती ईडी के सामने हुए पेश

हैदराबाद, (एजेंसी)। एक्टर राणा दग्गुबाती शहर में 2017 में ड्रग्स रैकेट के भंडाफोड़ के संबंध में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। वे इस मामले में चल रही धनशोधन जांच के तहत समन जारी किए जाने के बाद एजेंसी के समक्ष पेश हुए। एक्टर दग्गुबाती तेलुगू फिल्म उद्योग से जुड़े उन 10 अभिनेताओं व निर्देशकों में शामिल हैं जिन्हें ईडी द्वारा तलब किया गया है। पिछले साल 31 अगस्त से जाने-माने फिल्मकार पुरी जगन्नाथ, अभिनेत्री चार्मी कौर और रकुलप्रीत सिंह, अभिनेता नंदू केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश हो चुके हैं। दो जुलाई, 2017 को तेलंगाना के निषेध व उत्पाद शुल्क विभाग ने ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ किया था।

प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को तोहफा

केंद्र ने रबी फसल की एमएसपी में की बढ़ोतरी

सरसों व मसूर की एमएसपी 400-400 रुपए बढ़ी

नई दिल्ली ■ एजेंसी

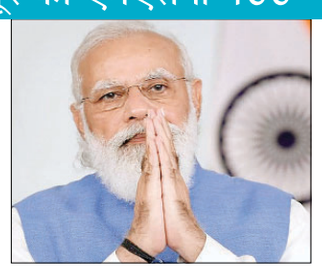

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है। कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा जारी आंदोलन के बीच ये फैसला लिया गया है।

केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपए तक पहुंच गई है। जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के मुताबिक, मसूर, रेपसीड तथा सरसों (400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी) के एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई है, इससे सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वक्त में अलग-अलग फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, उससे किसानों की आय दोगुनी करने की ओर एक अहम कदम बढ़ाया जाएगा।

किसानों के हित में एमएसपी में वृद्धि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चालू फसल वर्ष के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि किए जाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को किसानों के हित में बताया और कहा कि इससे जहां उन्हें अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा वहीं कई प्रकार की फसलों की बुवाई के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

किसानों के आंदोलन के बीच एमएसपी में बढ़ोतरी

बता दें कि सरकार की ओर से ये फैसला तब लिया गया है, जब कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पिछले करीब 10 महीने से पहले ही दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं को घेरे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। वहीं, अब एक बार फिर किसानों का आंदोलन तेज हुआ है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने जब रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया, तब हरियाणा के करनाल में किसान और स्थानीय प्रशासन आमने-सामने है। किसान संगठनों द्वारा यहां बीते दिनों हुए लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है।

कपड़ा उद्योग: पांच साल में 10,683 करोड़ के प्रोत्साहन की घोषणा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच साल में 10 हजार 683 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह योजना उत्पादन से जुड़ी होगी और 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का कारोबार करने वाले उद्योगों के लिए उपलब्ध होगी। यह योजना अगले पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इससे गुजरात, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के कपडा उद्योग पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का कारोबार

बासमती चावल के जीआई टैग में मिली मप्र को बड़ी कामयाबी

सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार की दलील को किया मंजूर

भोपाल (एजेंसी)।

प्रदेश में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग मिलने की उम्मीद फिर बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जीआई टैग देने की मांग वाली याचिका पर एमपी सरकार की दलील मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं कि मद्रास हाईकोर्ट मध्य प्रदेश (मप्र) में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग देने वाली याचिका पर पुनः सुनवाई करे।

दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। साल 2010 में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कश्मीर में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग मिला था। उसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बासमती चावल को जीआई टैग देने की मांग की गई थी। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानि एपीडा ने इसका विरोध किया था।

मप्र सरकार के तर्कों को ध्यान में रख पुनः फैसला लें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि बासमती चावल की खेती करने वाले मप्र के किसान भाई-बहनों के लिए राहत के साथ हर्ष और आनंद का यह क्षण है। प्रदेश के 13 जिलों में पैदा होने वाले बासमती को जीआई टैग देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मप्र की दलील को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मद्रास हाईकोर्ट इस मामले की पुनः सुनवाई करे और मप्र सरकार के तर्कों को ध्यान में रखकर पुनः फैसला ले। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के किसानों को शीघ्र न्याय मिलेगा और उनके श्रम का पूरा लाभ भी। अन्नदाता के हितों की रक्षा के लिए हम संकल्पित हैं।

प्रदेश के 13 जिलों में पैदा होता है बासमती चावल

सोयाबीन और कपास की खेती के लिए मशहूर मप्र के लगभग 13 जिलों में बासमती चावल की पैदावार होती है। इनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर जिले शामिल हैं। ये बासमती चावल बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है इसलिए मप्र शासन इसे जीआई टैग दिलाने का प्रयास कर रहा है।

प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर 0.02 फीसदी पर आई

सक्रिय केस हुए 137

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर 0.02 फीसदी हो गई है। सात सितंबर को पॉजिटिविटी दर 0.01 दर्ज की गई, जबकि आठ सितंबर को यह दर 0.01 बढ़कर 0.02 फीसदी पर पहुंच गई है। वहीं सक्रिय केस 137 हो गए हैं।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की है। कोरोना संक्रमण फिर से हर दिन दो गुना बढ़ रहा है। आठ सितंबर को प्रदेश में कुल 16 नए पॉजीटिव केस आए, जबकि 9 मरीज कोरोना मुक्त हो गए। जबलपुर में सबसे अधिक 12, भोपाल में 02, इंदौर में 01 और राजगढ़ में 01 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक कुल सात लाख 92 हजार 297 कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से सात लाख 81 हजार 644 ठीक हो गए । कुल संक्रमित मरीजों में से दस हजार 516 की मौत हो गई। दूसरी तरफ सरकार ने टीकाकरण कार्य को गति देते हुए अब तक 4 करोड़ 6 लाख 80 हजार पात्र लोगों को प्रथम डोज और 93 लाख 79 हजार को द्वितीय डोज दिया गया है।

प्रधान को यूपी व शेखावत को पंजाब की कमान

भाजपा ने पांच राज्यों के लिए नियुक्त किए चुनाव प्रभारी

धर्मेन्द्र प्रधान (यूपी)

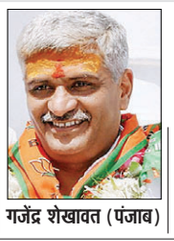
गजेंद्र शेखावत (पंजाब)

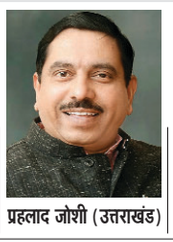
प्रहलाद जोशी (उत्तराखंड)

भूपेंद्र यादव (मणिपुर)

देवेंद्र फडणवीस (गोवा)

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भाजपा ने पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बुधवार को पार्टी प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। जिसमें धर्मेंद्र प्रधान उप्र के प्रभारी, मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव, पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तराखंड में प्रह्लाद जोशी और गोवा में देवेंद्र फडणवीस भाजपा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल और शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी, सांसद सरोज पांडे, सांसद विवेक ठाकुर और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को सह प्रभारी बनाया गया है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर संगठन प्रभारियों की भी नियुक्ति की गयी है। इनमें अरविंद मेनन, संजीव चौरसिया, संजय भाटिया, सत्या कुमार, सुधीर गुप्ता और सुनील ओझा शामिल हैं। पंजाब के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी जबकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी , मीनाक्षी लेखी और सांसद विनोद चावड़ा को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं जबकि सांसद लॉकेट चटर्जी और पार्टी प्रवक्ता सरदार आर पी सिंह सह प्रभारी होंगे। आगामी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और दर्शाना जर्दोष को सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर का चुनाव प्रभार देखेंगे तथा केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल सह प्रभारी होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को गोवा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है।

उत्तराखंड के पूर्व मंत्री पंवार भाजपा में

उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह पंवार बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। श्री पंवार ने यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष कौशिक और भाजपा के मीडिया प्रमुख राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर श्री पंवार ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा में शामिल होंने पर वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों से प्रभावित हैं।

रूस से बातचीत में भारत ने दो टूक कहा, तालिबान को लेकर पाकिस्तान की भी तय हो जिम्मेदारी

नई दिल्ली। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने वहां सरकार चलाने को लेकर वैश्विक विरादरी से जो वादा किया है अगर उस पर वह खरा नहीं उतरता है तो इसके काफी दूरगामी असर होंगे। यही नहीं, पाकिस्तान को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश में आतंकवादी वारदातों को बढ़ावा देने के लिए ना हो। यह बात भारत ने पिछले कुछ दिनों के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और रूस को साफ तौर पर बताया है।

अफगानिस्तान को लेकर वैश्विक शक्तियों के समक्ष भारत की दो टूक- भारत के दौरे पर पहुंचे रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव जनरल निकोले पेत्रुशेव ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग से मुलाकात की। इसके अलावा रूसी दल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के नेतृत्व में भारतीय दल की बैठक हुई। इन सभी बैठकों में भारत ने बगैर किसी लाग लपेट के यह बताया कि अफगानिस्तान के हालात सीधे तौर पर उसकी सुरक्षा से जुड़े हैं, लिहाजा वह हर सतर्कता बरतेगा।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए के प्रमुख विलियम बे र्न्स के साथ मंगलवार को बैठक में भी डोभाल ने भारत का यही रख रखा था। रूस और अमेरिका के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की यात्रा से पहले माना जा रहा है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एमआइ के प्रमुख ने भी हाल ही में भारत की गोपनीय यात्रा की थी। सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर बे र्न्स और एमआइ प्रमुख की यात्राओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सीआइए प्रमुख के बुधवार को अफगानिस्तान व पाकिस्तान जाने की भी अपुष्ट खबरें हैं। सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान के हालात पर भारत सीधे तौर पर कई स्तरों पर अमेरिका, रूस व दूसरे देशों के साथ संपर्क में है। इन देशों को भारत यह भी बता रहा है कि तालिबान को पाकिस्तान से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तालिबान की सत्ता आने के बाद पाकिस्तान की यह खास तौर पर जिम्मेदारी है कि वह अफगानिस्तान को आतंकवाद का गढ़ नहीं बनने दे। तालिबान को एक समग्र व आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने वाले सत्ता के तौर पर प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सभी की है लेकिन तालिबान की तरफ से अभी तक इस बारे में साफ संकेत नहीं दिया गया है। खास तौर पर मंगलवार को जिस तरह की सरकार का गठन किया गया है वह ज्यादा चिंता की बात है।

पेत्रुशेव और डोभाल के बीच हुई बैठक में तालिबान व उसकी नीतियों का मुद्दा ही सबसे अहम रहा। भारत व रूस का मानना है कि तालिबान को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे उसके किसी भी पड़ोसी देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिले।

भारत या मध्य एशियाई देशों में इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने या आतंकी संगठनों को प्रशिक्षण व हथियार देने को लेकर भी तालिबान को स्पष्ट तौर पर रोक लगाने का संकेत देना होगा। रूस की तरफ से बताया गया है कि मोदी और पेत्रुशेव के बीच अफगानिस्तान के संदर्भ में बात हुई और दोनों ने महसूस किया कि अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ।

पैरालिंपिक में ऐतिहासिक सफलता पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर- भविष्य की तैयारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे

नई दिल्ली । केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 5 स्वर्ण और 8 रजत सहित कुल 19 पदक जीत कर इतिहास रचने वाले भारत के पैरा-एथलीटों को सम्मानित किया। केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर खेल विभाग के सचिव श्री रवि मित्तल, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी पर उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अनुराग ठाकुर ने सभी पैरा एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। श्री ठाकुर ने कहा, मुझे याद है 2016 के पैरालंपिक में, भारतीय दल के 19 पैरा-एथलीटों ने भाग लिया था, जबकि इस साल देश ने 19 पदक जीते हैं!

आपने हमें दिखाया कि मानवीय भावना सबसे शक्तिशाली है! हमारी पदक तालिका में लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है। पहली बार हमने टेबल टेनिस में पदक जीते हैं, तीरंदाजी में कई पदक जीते हैं, कैनोइंग और पावरलिफ्टिंग में पहली बार प्रतिस्पर्धा की है। हमने दो विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की तथा हमने और भी कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारत के पैरा-एथलीटों ने एक आदर्श पोडियम फिनिश दिया!

श्री ठाकुर ने कहा, ÷अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एथलीट्स को

सहायता देने में सरकार के दृष्टिकोण में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है। सरकार सुविधाओं और वित्त पोषण के साथ भारत के पैरालंपियन्स की सहायता करना जारी रखेगी ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। हम, हमारे पैरालंपियन्स को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए और अधिक प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि वे नियमित रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने कौशल को निखार सकें।÷ उन्होंने आगे कहा, ÷सरकार भारत के पैरालंपियन्स को सुविधाओं और वित्त पोषण के साथ मदद देना जारी रखेगी ताकि पैरा-एथलीट 2024 और 2028 ओलंपिक में और भी अधिक पदक हासिल कर सकें।

सभी पैरा-एथलीट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) का हिस्सा हैं और इस योजना के तहत एथलीट्स को अधिक से अधिक सहायता देने के लिए योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा व मजबूत किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की हमारी प्रतिबद्धता का भी एक हिस्सा है।

श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि एथलीटों के असाधारण प्रदर्शन ने देश में पैरा-स्पोर्ट्स के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है। सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित की हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी खुद खिलाड़ियों से बात करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वास्तव में पिछली बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री जी ने पैरा-एथलीटों और उनके परिवारों से बातचीत करते हुए लगभग दो घंटे व्यतीत किए। इसका समाज के हर वर्ग पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वह व्यक्तिगत, कॉरपोरेट, खेल संघ या कोई अन्य संगठन हो।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री रिजिजू ने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि आपने भारत को गौरवान्वित किया है। श्री रिजिजू ने कहा, टोक्यो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी पैरा-एथलीट हमारे हीरो हैं।

आप सभी हर एक के लिए प्रेरणा हैं। आपने दिखाया है कि अगर आप सपने देखने की हिम्मत करते हैं तो सब कुछ संभव हो सकता है। श्री रिजिजू ने कहा कि हर खिलाड़ी की कहानी प्रेरणा देती है। देश में खेल संस्कृति तब स्थापित होती है जब खिलाड़ियों को हीरो के रूप में माना जाता है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं यह कह सकता हूं कि खेल संस्कृति अब भारत में आ गई है और प्रधानमंत्री ने इस परिवर्तनकारी बदलाव का नेतृत्व किया है।

संक्षिप्त समाचार

केंद्र ने उत्तर प्रदेश में पशुपालन, डेयरी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में पशुपालन और डेयरी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और राज्य सरकार से पशु पालक किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने को कहा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक समीक्षा बैठक में संजीव कुमार बालियान और एल मुरुगन भी शामिल हुए। दोनों मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं।केन्द्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के पशुपालन और डेयरी मंत्री के साथ यह समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रूपाला ने राज्य में भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा की और ब्रीडर फार्म उद्यमों तथा चारा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों पर खास जोर देने के लिए कहा। उन्होंने मौजूदा पशु बीमा का और विस्तार करने तथा पशुपालक किसानों के लिए अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को बढ़ावा देने की सलाह भी दी।

फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप जारी, अब तक 55 लोगों की मौत

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप जारी है और यहां अब तक इस बीमारी से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार प्रेमी ने बुधवार को बताया कि पूरे जिले में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें अधिकांश बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिले में पिछले तीन दिनों से डेंगू और वायरल से किसी की भी मौत नहीं हुई है। हालांकि अपुष्ट तौर पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू और वायरल से रोजाना औसतन पांच लोगों की मौत हो रही हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में डेंगू और वायरल के 171 नए मरीज भर्ती किए गए जबकि 160 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इसके अनुसार, डेंगू के जो रैपिड टेस्ट किए गए हैं उनमें 342 में से 107 सैंपल पॉजिटिव आए हैं जबकि डेंगू के एलिसा टेस्ट में 172 पॉजीटिव एवं आईजीएम 257 में से 140 पॉजिटिव आए हैं। इसमें कहा गया है कि 140 टेस्ट कोविड-19 के भी किए गए जिसमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने चार सदस्यों की एक समिति बनाई है जो अब तक हुई 55 मौतों के बारे में मृतकों के घर जाकर जानकारी एकत्र करेगी ताकि मौतों की वजह के प्रकार का पता लगाया जा सके।

गोवा भाजपा ने विधानसभा चुनाव में फडणवीस को प्रभारी बनाने पर जताई खुशी

पणजी। गोवा में भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने पर खुशी जताई है। गोवा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उरफान मुल्ला ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, यह बहुत अच्छा अहसास है कि देवेंद्र फडणवीस गोवा के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी होंगे। उनका अनुभव पार्टी को राज्य में बहुमत की सीटें जीतने में मदद करेगा। पूर्व भाजपा विधायक और प्रवक्ता सिद्धार्थ कुनकालिनकर ने भी ट्वीट किया, गोवा बीजेपी गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव को देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी के नियुक्ति का स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लोगों के विश्वास को बनाए रखेंगे। 22 में 22 प्लस। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को पिछले महीने गोवा चुनावों का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रभारी नियुक्त किया था। राज्य भर के राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रहे हैं, जो 2022 की शुरूआत में होने वाले हैं।

तेलंगाना में भाजपा ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने का किया वादा

हैदराबाद। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने वादा किया है कि अगर राज्य में सत्ता में आए तो पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कानून की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी। संजय ने अपनी प्रजा संग्राम पदयात्रा के तहत संगारेड्डी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह वादा किया। उन्होंने कहा, भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में, मैं घोषणा कर रहा हूं कि 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी और हम जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाएंगे। संजय, जो लोकसभा के सदस्य भी हैं, ने कहा कि भाजपा की नीति है कि एक बच्चा आदर्श है और अधिकतम सीमा दो है। उत्तर प्रदेश ने दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जल्द ही एक कानून लाने का प्रस्ताव रखा। भाजपा नेता ने धर्म आधारित आरक्षण को लागू करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे कमजोर वर्गों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हाथी के हमले में ग्रामीण की हुई मौत

छत्तीसगढ़। महासमुंद जिले के एक गांव में जंगली हाथी के हमले में एक बुजुर्ग ग्रामीण की मौत हो गई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। महासमुंद जिले के वन विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जिले के सिरपुर क्षेत्र के अंतर्गत बंदोरा गांव के करीब हाथी के हमले में नारायण साहू (60)की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग को जानकारी मिली है कि अचानकपुर गांव निवासी नारायण साहू मंगलवार को एक अन्य व्यक्ति राजकुमार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर झलप गांव गये थे और देर शाम वापसी के दौरान बंदोरा गांव के करीब उनका सामना हाथी से हो गया। उन्होंने बताया कि हाथी के सामने आते ही राजकुमार वहां से भाग गया लेकिन इस दौरान हाथी ने नारायण साहू को कुचलकर मार डाला।

केरल के एक परिवार के लिए निपाह का मतलब 'मौत', अब भी डर के साये में

तिरुवनंतपुरम। (एजेंसी)।

तीन साल पहले जब सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी कि किसी घातक संक्रामक बीमारी ने उनके 'एक्का' (बड़े भाई) की जान ले ली तो मोहम्मद मुथालिब ने अपने परिवार के बारे में ''फर्जी खबर'' पर आक्रोश महसूस किया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ''निपाह'' बीमारी के बारे में नहीं सुना था। जब तक 19 वर्षीय छात्र मुथालिब को इस संक्रामक बीमारी की गंभीरता का पता चलता तब तक यह वायरस उनके परिवार के चार सदस्यों की जान ले चुका था। इस आघात से मुथालिब और उनकी मां मरियम्मा को गहरा सदमा पहुंचा।

केरल एक बार फिर निपाह वायरस के संक्रमण की चपेट में है और हाल में इस बीमारी से 12 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई। मुथालिब ने 2018 में अपने परिवार पर आई विपदा को याद करते हुए कहा कि यह रोग उनके परिवार के लिए मौत, डर और सामाजिक बहिष्कार का कारण बना। मुथालिब ने कहा, ''ऐसे कई लोग थे जो हमसे बात करने से डर रहे थे, घटना के एक साल गुजर जाने के बाद भी इस बीमारी ने हमारे परिवार को काफी प्रभावित किया। मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ रहा... जिस डर और तनाव सब गुजरे होंगे, उन्हें मैं समझ सकता हूं।'' उत्तरी कोझिकोड के गांव सूप्पीक्काडा के निवासी मुथालिब ने निपाह वायरस के संक्रमण के कारण अपने पिता, दो भाइयों और बुआ को खो दिया। केरल 2018 में पहली बार इस वायरस के संक्रमण से प्रभावित हुआ। संक्रमण से मरने वालों में शामिल, मुथालिब के भाइयों में से एक मोहम्मद साबिथ राज्य में निपाह से जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति थे।

हालांकि, शुरू में संक्रमण के कारण साबिथ की मौत के कारणों की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन परिवार के एक अन्य युवक मोहम्मद सलीह की अचानक मौत ने डॉक्टरों के बीच संदेह पैदा कर दिया और नमूनों की जांच ने राज्य में वायरल संक्रमण की मौजूदगी की पुष्टि की।अस्पताल में भर्ती मुथालिब की बुआ मरियम ने भी बाद में निपाह के कारण दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने शुरू में मुथालिब के 60 वर्षीय पिता मूसा मुसलियार की जान बच जाने को लेकर उम्मीद जताई थी, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार की एक अन्य महिला सदस्य भी संक्रमित हो गई थीं, लेकिन एर्नाकुलम जिले के एक बड़े अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी जान बच गई।

मुथालिब ने कहा, ''उन दिनों मेरे परिवार को जो सदमा लगा था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पांच सदस्य इस वायरस से संक्रमित हुए थे और उनमें से चार की जान चली गयी।'' पिछले हफ्ते कोझिकोड में 12 वर्षीय लड़के ने निपाह वायरस के संक्रमण से दम तोड़ दिया जिसके बाद केरल में फिर से इस घातक बीमारी की वापसी का संकेत मिला है। फिलहाल, बच्चे के सीधे और परोक्ष रूप से संपर्क में आए 257 लोगों की सूची तैयार की गई है। इनमें से 141 स्वास्थ्यकर्मी हैं और उनमें से किसी में भी कोई गंभीर लक्षण नहीं हैं।

पटना में तेजस्वी और चिराग की मुलाकात, गठबंधन के सवाल पर दिया यह जवाब

पटना (एजेंसी)।

लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान के बाद आज पटना में चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कई कयासों

को बल मिलने लगा है। हालांकि मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव से मिला हूं। उन्हें 12 सितंबर को होने वाली पिता की बरखी में आमंत्रित करने के लिए आया था। मैं कल दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से ही मिलूंगा।

चिराग ने आगे कहा कि मेरा उद्देश्य उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित करना है जिन्होंने मेरे पिता के साथ काम किया है। मैं मुख्यमंत्री से भी मिल सकता हूं। वहीं, गठबंधन को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम वही कह रहे जो कहना चाहते हैं। लालू जी ने जो कहा था उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते।

आपको बता दें कि बिहार में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के गठबंधन के सवाल पर लालू यादव ने कहा था कि लोजपा में जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं है। चिराग पासवान आज भी लोजपा के नेता बने हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तेजस्वी और चिराग साथ आएं। बिहार में एनडीए की जीत को लेकर लालू यादव ने कहा कि हम बिहार में सरकार बनाने वाले थे। मेरे जेल में होने के बावजूद मेरे बेटे तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी गठबंधन से अकेले लड़ाई लड़ी। हमें धोखे में रखा गया और 10-15 वोटों से हराया गया।

अगले 20 वर्षों में करीब 350 विमानों की खरीद पर कर रहे हैं विचार : वायुसेना प्रमुख

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

भारतीय वायुसेना अगले दो दशकों में करीब 350 विमानों की खरीद पर विचार कर रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र विषय पर एक सम्मेलन में चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने अपने संबोधन में चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय वायुसेना की संपूर्ण ताकत को और मजबूती देने के लिए विषम क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, ÷उत्तरी पड़ोसी को देखते हुए, हमारे पास आला दर्जे की प्रौद्योगिकियां होनी चाहिए जिन्हें सुरक्षा कारणों से हमारे अपने उद्योग द्वारा देश में ही बनाया जाना चाहिए।÷ विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने पर जोर देते हुए एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना अगले दो दशकों में देश से ही लगभग 350 विमान खरीदने पर विचार कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह एक मोटा-मोटा अनुमान है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तेजस हल्के लड़ाकू विमान परियोजना ने भारत में एयरोस्पेस उद्योग में भरोसा पैदा किया है और यह भी विश्वास जगाया है कि इसके और विकसित होने की असीम संभावनाएं हैं।

राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांट रहे हैं ओवैसी: बीजेपी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

बीजेपी ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने का आरोप लगाया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ओवैसी का समाज को विभाजित करने और सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा देकर हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ने का इतिहास रहा है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर नजर रखते हुए, वह राजनीतिक लाभ लेने के लिए सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत करता है। गंगा-जमुनी तहजीब देश में सदियों से एक परंपरा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है और हम भागवत जी के इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक जैसा है। सिद्दीकी ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म की राजनीति करने वाले ओवैसी जैसे लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज में जहर घोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुसलमानों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके परिवार ने कभी भी उनके उत्थान और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, वहीं ओवैसी जैसे लोग समाज को बांट रहे हैं। सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदाता उन्हें करारा जवाब देंगे। ओवैसी ने मंगलवार को अयोध्या से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने पार्टी अभियान की शुरूआत की।

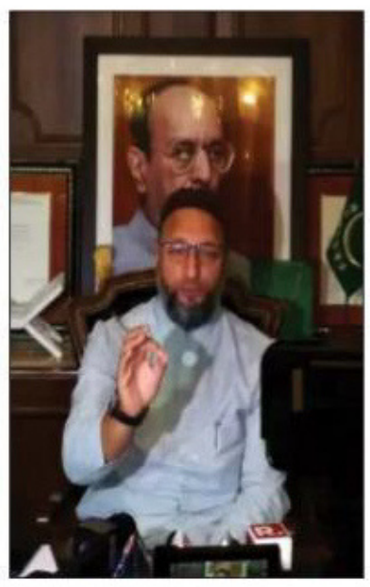

फारुक अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद, कहा– अफगानिस्तान में तालिबान अच्छी तरह से करेगा शासन

श्रीनगर। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन हो गया है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारुख अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने उम्मीद जताई कि तालिबान इस्लामी उसूलों का पालन करते हुए अच्छी सरकार चलाएं।

सभी के साथ करें इंसाफ !

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान एक अलग देश है। जो वहां पर आए हैं उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है। उम्मीद करूंगा कि वे सभी से इंसाफ करेंगे और इस्लामी उसूल पर अच्छी हूकूमत चलाएंगे। उन्हें हर मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुक पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने नई सरकार का गठन किया है। जिसमें मुल्ला हसन अखुंद को सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। जबकि मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी को उप प्रधानमंत्री का पद मिला। नई सरकार की कैबिनेट में हक्कानी ग्रुप के 4 कमांडरों को भी जगह मिली। हालांकि तालिबान का असल चेहरा भी सामने आ गया।

भाजपा ने साधा निशाना

तालिबान ने सरकार गठन में महिलाओं और अफगानियों को शामिल करने की बात कही थी लेकिन किसी को भी जगह नहीं दी गई। वहीं, फारुख अब्दुल्ला की टिप्पणी पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। भाजपा नेता निर्मल सिंह ने कहा कि तालिबान महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहा है लेकिन फारुक अब्दुल्ला ने उनका पक्ष ले रहे हैं।

केंद्र ने न्यायालय को बताया, सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं की भर्ती का फैसला किया है

नई दिल्ली (एजेंसी)।

केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ को बताया कि सरकार के साथ ही सशस्त्र बलों के उच्च स्तर पर फैसला लिया गया है कि एनडीए के जरिए स्थायी कमीशन के लिए महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी। भाटी ने हलफनामे के जरिए जानकारी देने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी। न्यायालय ने कहा कि वह समय-समय पर प्राधिकारियों को खुद इसे करने के लिए प्रेरित करता रहा है और उसका मानना है कि वे इसे करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। पीठ ने कहा, ''ऐसी राय है कि जब कुछ नहीं होता तो अदालत आगे आती है। आपको आश्वस्त कर दूं कि अदालत को हस्तक्षेप करने में खुशी नहीं होती और हम चाहेंगे कि सशस्त्र बल खुद यह करें। वे देश के सम्मानित बल हैं लेकिन लैंगिक समानता पर उन्हें और करने की आवश्यकता है और कभी-कभी प्रतिरोध अच्छा साबित नहीं होता।'' पीठ ने कहा, ''मैं खुश हूं कि सशस्त्र बलों के प्रमुख ने एक सकारात्मक फैसला लिया है। रिकॉर्ड में रखिए, हम मामले पर सुनवाई करेंगे। हम इस रुख से खुश हैं।

हमें अगले हफ्ते मामले पर सुनवाई करने दीजिए। सुधार एक दिन में नहीं होते। हम इससे अवगत हैं।'' अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि ऐसा विचार पहले ही चल रहा था लेकिन वह केवल शुरुआती स्तर पर था। मामले पर सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद की तारीख तय की गयी है। उच्चतम न्यायालय वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में प्रतिष्ठित एनडीए में लैंगिक आधार पर योग्य महिलाओं को भर्ती नहीं करने का मुद्दा उठाते हुये इसे समानता के मौलिक अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन बताया गया था।

हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा पाकिस्तान, अभद्र भाषा के लिए यूएन फोरम का करता है इस्तेमाल: भारत

नई दिल्ली/संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

भारत ने पाकिस्तान पर हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने और अभद्र भाषा के लिए शांति की संस्कृति पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने मंगलवार को महासभा को बताया, हमने पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत के खिलाफ अभद्र भाषा के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का फायदा उठाने के लिए आज एक और प्रयास देखा है, भले ही वह घर और अपनी सीमाओं पर हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा हो। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम की टिप्पणी का एक निष्क्रिय संदर्भ देते हुए उन्होंने शांति की संस्कृति पर उच्च स्तरीय मंच को अपने संबोधन में कहा, हम ऐसे सभी प्रयासों को खारिज और निंदा करते हैं। अकरम ने अपने नौ पैराग्राफ के भाषण के छह पैराग्राफ भारत और आरएसएस को समर्पित किए और महासभा को हिंदुत्व का सामना करने के लिए कहा है।

हालांकि अक्सर संयुक्त राष्ट्र में भाषण इस विषय से हटकर होते हैं, अकरम का संबोधन इस मायने में असामान्य था कि इसने लगभग पूरी तरह से एक सदस्य देश में एक संगठन को इसके लिए एक अपशब्द का उपयोग करके लक्षित किया। पाकिस्तान की पहचान किए बिना, मैत्रा ने वहां से निकलने वाले धर्म आधारित आतंकवाद की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद, जो असहिष्णुता और हिंसा की अभिव्यक्ति है, सभी धर्मों और संस्कृतियों का विरोधी है। दुनिया को चिंतित होना चाहिए। आतंकवादियों द्वारा जो इन कृत्यों को सही ठहराने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं और जो इस खोज में उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और सदस्य कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर चयन करने से बचना चाहिए जो शांति की संस्कृति में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से धर्म के मुद्दे पर चर्चा का आधार बनाने के लिए निष्पक्षता, गैर-चयनात्मकता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को लागू करने के अपने आह्वान को दोहराता है। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण को याद किया जिसमें उन्होंने सभी धर्मों की महानता को स्वीकार करने के भारत के सभ्यतागत लोकाचार पर जोर दिया था। उन्होंने कहा, भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। बहुलवाद की हमारी अवधारणा सर्व धर्म संभव के हमारे प्राचीन लोकाचार पर आधारित है जिसका मतलब है सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। हालांकि कोविड -19 महामारी ने मानवता की अन्योन्याश्रयता को सामने लाया, लेकिन असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, हम इन्फोडेमिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने वाले भाषणों में वृद्धि और समुदायों के भीतर नफरत पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इंफोडेमिक को एक बीमारी के प्रकोप के दौरान डिजिटल और भौतिक वातावरण में झूठी या भ्रामक जानकारी सहित बहुत अधिक जानकारी के रूप में परिभाषित करता है, जो स्वास्थ्य अधिकारियों के अविश्वास का कारण बनता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को कमजोर करता है और बीमारी के प्रकोप को तेज या लंबा कर सकता है। मैत्रा ने याद किया कि पिछले साल जून में भारत ने 12 देशों के साथ कोविड-19 के संदर्भ में इन्फोडेमिक पर क्रॉस-रीजनल स्टेटमेंट को सह-प्रायोजित किया था।

संक्षिप्त समाचार

मयूर विहार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने मयूर विहार फेस-2 का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद भावना मलिक और निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महापौर को क्षेत्रीय पार्षद भावना मलिक ने पूर्वी विनोद नगर में जलभराव की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने महापौर को बताया कि बरसात के दौरान एनएच 9 का पानी पूर्वी विनोद नगर की गलियों में भर जाता है। जिससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि एनएच-9 अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्षेत्र के लोगों को बरसात के दिनों में नारकीय जीवन गुजारना पड़ता है। महापौर ने कहा कि वह इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। महापौर को आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने सुपर शाइन चौक, पूर्वी विनोद नगर में अतिक्रमण की समस्या की शिकायत की। स्थानीय लोगों ने कहा कि अतिक्रमण के चलते फुटपाथ पर चलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा आवारा पशुओं ने भी समस्या को और बढ़ा दिया है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। महापौर ने अपने दौरे के दौरान निगम स्कूलों का भी जायजा लिया। महापौर ने निगम स्कूलों में व्यवस्था का संतोषजनक पाया। निगम स्कूलों में बच्चों के खेलने व कलात्मक गतिविधियों के लिए बेहतर व्यवस्था नजर आई।

केशवपुरम जोन में डेंगू की रोकथाम के लिए चलाया गया महाअभियान

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि जोन के सभी 18 वार्डों में डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए संयुक्त महाअभियान चलाया गया। इस महाअभियान में जोन के समस्त अधिकारी उपस्थित थे और यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। इस अभियान की शुरूआत केशवपुरम जोन के अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बी-3, अशोक विहार के बड़े नालों की सफाई व दवाईयों के छिडकाव से की गई जिसमें पावर स्प्रे टैंकर का इस्तेमाल किया गया। वर्मा ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए वार्ड अनुसार प्रत्येक दिन के लिए एक सूची तैयार की गई है जिसमें वार्ड के संबंधित पार्षद के साथ अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बड़े-बड़े नालों की सफाई बड़े पावर स्प्रे टैंकर के द्वारा तथा घरों के अंदर व छोटी नालियों की सफाई व दवाई छिड़काव छोटे मशीनों व फौगिंग मशीनों के माध्यम से करायी जाएगी।

दिल्ली में आए सामने कोरोना के 41 नए मामले

नई दिल्ली (एजेंसी)।

राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। इस दौरान संक्रमण की दर 0.05 प्रतिशत रही। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि राजधानी में कोरोना की प्रतिदिन पॉजिटिविटी दर इस समय 0.05 प्रतिशत है जो कि एक दिन पहले की तुलना में 0.02 प्रतिशत कम है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,079 नमूनों की जांच की गई। इसी अवधि में 13 और लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो गए और 107 लोग अभी भी होम आइसोलेशन में है। इस समय राजधानी में कोरोना के 414 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 14,38,082 और कुल मृतकों की संख्या 25,083 है। राजधानी में कुल समग्र पॉजिटिविटी दर 4.49 प्रतिशत और केस मृत्यु दर 1.74 दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के पहले 2 मार्च को मौत का आंकड़ा शून्य था और उस दिन एक दिन में कोरोना के 217 मामले दर्ज किए गए थे तथा पॉजिटिविटी दर 0.33 थी। कोरोना की दूसरी लहर ने राजधानी में अप्रैल और मई में कहर बरपाया था।

बैठक दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की बैठक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद थे।

अब दिल्ली सरकार देगी पर्यावरण परियोजनाओं को मंजूरी: गोपाल राय

नई दिल्ली, प्रफुल्ल राय(शिवालिक)।

केंद्र सरकार के फैसले का नहीं करना पड़ेगा इंतजार

दिल्ली सरकार ने स्टेट लेवल इनवायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी के गठन को अधिसूचित कर दिया है। बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि समिति बनने से आवेदनों का निस्तारण करने में आसानी होगी। साथ ही, परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के लिए अब केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अब दिल्ली सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य में पर्यावरण प्रभाव का आंकलन अधिक मजबूती और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर केजरीवाल सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार मानकों से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। दिल्ली के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का गठन 3 साल के कार्यकाल के लिए किया गया है। एसईआईएए का अध्यक्ष सर्वज्ञ कुमार श्रीवास्तव और सदस्य के रूप में रीना गुप्ता को नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (पर्यावरण) इसके सदस्य सचिव होंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अब पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता वाली बी श्रेणी की परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब दिल्ली सरकार द्वारा ही बिना विलंब किए मंजूरी दी जाएगी। साथ ही, हम इस व्यवस्था को अधिक मजबूत और पारदर्शी भी बनाएंगे। पर्यावरण संरक्षण दिल्ली सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार ने 2020 में विशेषज्ञों के नामों के साथ एसईआईएए-एसईएसी के पुनर्गठन के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। कई बैठकों के बाद अंततः अधिसूचना जारी की गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण नियमों के अनुसार सभी ए श्रेणी की परियोजनाओं (मेगा परियोजनाओं) को एमओईएफसीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जबकि सभी बी श्रेणी की परियोजनाओं (बड़ी परियोजनाओं) को राज्य स्तर पर अनुमोदित किया जाता है।

मासिक बैठक से निर्णय लेने में आएगी तेजी, कम होगी पेंडेंसी

गोपाल राय ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से मासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिससे निर्णय लेने में तेजी आएगी और मामलों की पेंडेंसी कम होगी। प्राधिकरण उन परियोजना स्थलों के नियमित निरीक्षण को अनिवार्य कर सकता है, जिन्हें पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया सके कि वे सभी मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं। यदि किसी परियोजना में उल्लंघन में पाया जाता है? तो प्राधिकरण पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्णय ले सकता है। किसी भी परियोजना स्थल पर कोई भी नागरिक नियमों का उल्लंघन पाता है, तो वह प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।

पराली से प्रदूषण को रोकने के लिए बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सर्दी में पराली जलाए जाने और दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की रणनीति पर चर्चा के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिल्ली में हर साल सर्दी में कई कारणों से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी जाती है, जिसमें पड़ोसी राज्यों में पराली जलाया जाना भी शामिल है। एक अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरण विभाग और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। गोपाल राय के अनुसार सरकार अगले सप्ताह एक शीतकालीन कार्य योजना तैयार करना शुरू कर देगी। राय ने मंगलवार को सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाने की मांग की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से मांग की कि वे वायु गुणवत्ता खराब होने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी द्वारा पिछले साल उठाए गए कदमों को लागू करें। मंत्री ने कहा कि पिछले साल हमने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया। प्रदूषण के खिलाफ कोशिशों की निगरानी और समन्वय के लिए ग्रीन वार रूम बनाया।

हमने धूल रोधी अभियान शुरू किया जिसे अन्य राज्यों के एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में दोहराया जा सकता है। राय ने कहा था कि प्रतिनिधियों का एक समूह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर केंद्रीय आयोग से मुलाकात करेगा और संयुक्त कार्ययोजना पर चर्चा करेगा जिसे दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किया जा सकता है।

पूजा करने की जगह कोरोना पीड़ितों की मदद करे सरकार: रामवीर सिंह बिधूड़ी

दीपावली पूजन पर सरकार ने खर्च किए थे 6 करोड़ रुपए

नई दिल्ली,(आनंद राय)।

आगामी 10 सितंबर को दिल्ली सरकार की ओर से की जाने वाली गणेश चतुर्थी की पूजा को बहुत महंगा खर्च बताते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा की जाने वाली पूजा दिल्ली को बहुत महंगी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इस पूजा पर किए जाने वाला खर्च अगर दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट बनाने या कोरोना पीड़ितों को राहत देने के लिए खर्च किए जाए तो वह ज्यादा सार्थक होगा। बिधूड़ी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल 10 सितंबर को अपनी पूरी कैबिनेट और परिवार के साथ गणेश चतुर्थी की पूजा करने वाले हैं। ऐसी ही पूजा उन्होंने पिछले साल दिवाली पर भी की थी। पिछले साल दिवाली पर हुई 30 मिनट की पूजा पर सरकार का खर्चा 6 करोड़ रुपए आया था यानी हर मिनट की पूजा पर दिल्ली सरकार का 20 लाख रुपए खर्चा हुआ था। दिल्ली को यह पूजा बहुत महंगी पड़ती है। अब गणेश चतुर्थी पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री अपने परिवारों के साथ 30 मिनट की ही पूजा करने वाले हैं। इस बार का खर्चा संभवतः 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि दिल्ली के लोगों में ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है और वे पूजा-अर्चना में कहीं पीछे नहीं रहते। गणेश चतुर्थी की पूजा भी कोविड नियमों का पालन करते हुए वे अपने घरों पर ही कर लेंगे। सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री अपने परिवारों के साथ गणेश पूजा करते हुए जनता को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी राशि इस पूजा पर खर्च की जा रही है, अगर उससे दिल्ली में और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाते तो वह ज्यादा सार्थक होता। इसके अलावा सरकार ने कोरोना मृतकों को परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की थी लेकिन 25 हजार में से सिर्फ साढ़े 3 हजार लोगों के ही फार्म अभी तक मंजूर हो पाए हैं। उनके जख्मों पर मरहम रखने की बजाय सरकार उनके आवेदनों में आपत्तियां निकालकर उन्हें 50 हजार रुपए भी नहीं दे रही। बिधूड़ी ने पूछा है कि क्या ऐसी हालत में गणेश चतुर्थी की पूजा के नाम पर दोनों हाथों से करोड़ों रुपए लुटाना उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर नहीं होगा? क्या टैक्स पेयर्स के खून-पसीने की कमाई से करोड़ों रुपए खर्च करना न्यायसंगत है?

बिधूड़ी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल 10 सितंबर को अपनी पूरी कैबिनेट और परिवार के साथ गणेश चतुर्थी की पूजा करने वाले हैं। ऐसी ही पूजा उन्होंने पिछले साल दिवाली पर भी की थी।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने शिक्षकों को निगम पुरस्कार से सम्मानित किया

नई दिल्ली (एजेंसी)।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा बैजयंत पांडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, महापौर मुकेश सुर्यान व शिक्षा समिति की अध्यक्षा नीतिका शर्मा ने निगम मुख्यालय में आयोजित शिक्षक दिवस कार्यक्रम में 30 शिक्षकों को निगम पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही कोरोनाकाल में जान गवाने वाले दिव्यंगत शिक्षक विश्वशांत गोड की धर्मपत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रु का चेक प्रदान किया। कोरोना महामारी के दौरान दिव्यंगत शिक्षक विश्वशांत गोड ने कोरोनायोद्धा के रूप में कार्य करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए वे कुतुब विहार निगम विद्यालय में कार्यरत थे। इस अवसर पर उप-महापौर पवन शर्मा, स्थायी समिति के अध्यक्ष कर्नल बीके ओबरॉय, नेता सदन इंद्रजीत सहरावत, स्थायी समिति की उपाध्यक्षा पूनम भाटी, शिक्षा समिति की उपाध्यक्षा आभा चौहान, अतिरिक्त आयुक्त एए ताजिर, निदेशक शिक्षा प्रदीप कुमार व अन्य पार्षदगण तथा निगम अधिकारी उपस्थित थें। दक्षिणी निगम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए इस वर्ष 2 प्रधानाचार्य-26 प्राथमिक शिक्षकों व 2 नर्सरी शिक्षकों को निगम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही गुरू का अहम योगदान रहा है। उन्होंनें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है जिससे शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंनें कहा कि निगम स्कूलों में भी नई शिक्षा नीति जल्द से जल्द लागू की जाएगी ताकि बड़े स्तर पर विद्यार्थी लाभांवित हो सकें। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोनाकाल में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद रहे, फिर भी शिक्षकों ने अपने प्रयासों से बच्चों की शिक्षा को जारी रखा। कोरोनाकाल में शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा देने के अलावा, विद्यालयों में जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन बांटने का कार्य भी किया।

निगम स्कूलों में भी नई शिक्षा नीति जल्द से जल्द लागू की जाएगी

दिल्ली में गणेश चतुर्थी के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)।

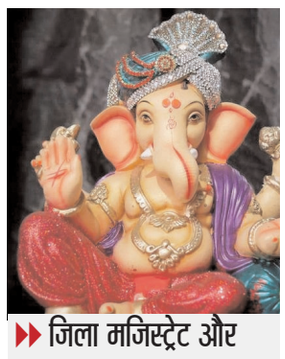

कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राजधानी में गणेश चतुर्थी पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी देने से मना कर दिया है। डीडीएमए की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि भगवान गणेश की प्रतिमाएं टेंट और पंडाल में नहीं स्थापित की जाएं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक स्थल पर लोगों की भीड़ नहीं जमा हो। बयान में कहा गया कि किसी तरह का जुलूस निकालने की भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। डीडीएमए ने लोगों से गणेश चतुर्थी का पर्व घरों में मनाने को कहा है। इस बयान में कहा गया कि इसी माह गणेश चतुर्थी है और कोविड-19 के हालात और लोगों के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पर्व से जुड़ा कोई भी आयोजन सार्वजनिक तौर पर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस को नजर रखने की निर्देश

शुभारंभ सॉफ्टवेयर के द्वारा सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्यों के लागत अनुमान व स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया संबंधित अन्य कार्य किए जाएंगे

महापौर ने प्राइस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया

नई दिल्ली,(रविशंकर तिवारी)।

महापौर मुकेश सुर्यान ने आयुक्त ज्ञानेश भारती की उपस्थिति में सिविक सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में प्राइस, प्रोजेक्ट इंफोरमेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि दक्षिणी निगम दिल्ली का पहला स्थानीय निकाय बना जहां इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्यों के लागत अनुमान व स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया संबंधित अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंनें कहा कि प्राइस,प्रोजेक्ट इंफोरमेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर कार्य प्रणाली में पारदर्शिता व कुशलता आएगी और बिना किसी विलंब के ऑनलाइन ही सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्यों की टेंडर प्रक्रिया से लेकर बिल भुगतान का कार्य हो जाएगा। इस अवसर पर एनआईसी की डीडीजी रचना श्रीवास्तव, उप-महापौर पवन शर्मा, स्थायी समिति के अध्यक्ष कर्नल बीके ओबरॉय,नेता सदन इंद्रजीत सहरावत, स्थायी समिति की उपाध्यक्षा पूनम भाटी, अतिरिक्त आयुक्त रमेश वर्मा,अतिरिक्त आयुक्त एए ताजिर, प्रमुख अभियंता पीसी मीणा, निदेशक आईटी भूपेश चौधरी व अन्य पार्षदगण तथा निगम अधिकारी उपस्थित थें। साथ ही एनआईसी की केरला टीम भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी। आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कहा कि पिछले एक वर्ष से हमारा यह प्रयास रहा कि इस सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द लागू किया जाए। एनआईसी के सहयोग से दक्षिणी निगम इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विभिन्न अभियांत्रिकी कार्यों की टेंडर प्रक्रिया से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से निपटा सकेगा। प्रथम चरण में कार्यों की लागत अनुमान व स्वीकृति दी जाएगी। दूसरे चरण में कार्यों को सौपने व टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। तीसरे चरण में प्रोजेक्ट व कार्यों का प्रबंधन व निरीक्षण और बिल भुगतान आदि किये जायेंगे। उन्होंनें कहा कि अभियांत्रिक विभाग के अभियंता व अन्य अधिकारियों को इस सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के दौरन 521 लागत अनुमान बनाए गए और 487 को प्राशासनिक स्वीकृति तथा 435 को तकनीकि स्वीकृति प्रदान की गई।

एनआईसी के सहयोग से दक्षिणी निगम इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विभिन्न अभियांत्रिकी कार्यों की टेंडर प्रक्रिया से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से निपटा सकेगा।

संपादकीय

कहीं बुलबुला न बन जाए यह तेजी

भारतीय शेयर बाजार में बहार दिख रही है। सूचकांक लगातार ऊंचाई का रिकॉर्ड बना रहा है। इससे निवेशक काफी ज्यादा खुश हैं। फरवरी से अब तक तकरीबन 30 शेयरों ने शत-प्रतिशत रिटर्न दिया है। निवेशकों के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों में ही 44.7 लाख खुदरा निवेशकों के खाते खुले हैं। तो क्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार भारतीय अर्थव्यवस्था की उम्मीद है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले हमें शेयर बाजार के गणित को समझना होगा। इसमें किसी कंपनी के शेयर दो वजहों से चढ़ते-उतरते हैं। पहली, उस कंपनी की मौजूदा दशा क्या है? और दूसरी, आने वाले समय में वह कैसा प्रदर्शन करेगी? यह तो तय है कि देश की अर्थव्यवस्था अभी 2019 के स्तर पर भी नहीं पहुंच सकी है। इसलिए जाहिर तौर पर लोग सूचीबद्ध कंपनियों के आगे बेहतर करने की उम्मीद में ही निवेश कर रहे हैं। इस सोच के वाजिब कारण हैं। मसलन, अभी निवेशक अधिकांशतः टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग जैसी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। चूंकि हमारी मांग में बदलाव आया है और हम बगल की दुकान से नहीं, बल्कि ऑनलाइन खरीदारी ज्यादा करने लगे हैं, इसलिए इन कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसी के कारण कुछ कंपनियों के आईपीओ आश्चर्यजनक रूप से काफी ज्यादा पर खुले। अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनियों के इतिहास ने भी निवेशकों को इन जैसी कंपनियों पर पैसा लगाने को प्रोत्साहित किया।

मगर सवाल यह है कि जब अर्थव्यवस्था की हालत खास्ता हो, तब निवेशकों की चांदी क्यों है? दरअसल, अभी बाजार में लिक्विडिटी, यानी तरलता (पूंजी) ज्यादा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कोरोना से लड़ रही हैं, इसलिए तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपने-अपने यहां लिक्विडिटी बढ़ाई है। व्यापारिक-वर्ग के हाथों में पैसे आने से वे निवेश की सोचने लगे हैं। चूंकि रियल एस्टेट में ज्यादा रिटर्न नहीं है, और बैंकों में भी ब्याज दरें कम कर दी गई हैं, इसलिए अच्छे रिटर्न की चाहत में शेयर बाजार उनके लिए सबसे मुफीद बन गए हैं। भारतीय शेयर बाजार इसलिए भी निवेशकों को लुभा रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। नतीजतन, यहां उन कंपनियों के दाम भी चढ़ने लगे हैं, जिनका भविष्य बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखता। यही वह बात है, जिससे हमें चिंतित होना चाहिए। शेयर बाजार में उन कंपनियों के निवेशक मुनाफे में रहते हैं, जो भविष्य में अच्छा रिटर्न देने का भरोसा देती हैं, लेकिन उन कंपनियों के निवेशकों को नुकसान हो सकता है, जिनके बदहाल होने की आशंका अधिक है। दिक्कत यह है कि किसी कंपनी का भविष्य पढ़ पाना आसान नहीं होता। कुछ कंपनियों का तो ठीक-ठीक आकलन किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर शेयरों की खरीद-बिक्री काफी कुछ अनुमान पर आधारित होती है। इसमें जो निवेशक बाजार को पढ़ सका, वह तो मुनाफे में रहेगा, लेकिन जो ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकता, उसे घाटा हो सकता है। एक दिक्कत यह भी है कि बाजार के चढ़ने से शेयर का मूल्य-आय अनुपात (कंपनी के शेयर का मूल्य और शेयर से अर्जित आय का अनुपात) बढ़ जाता है। अभी भारतीय शेयर बाजार का यही हाल है। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब यह टूटेगा (जिसकी आशंका ज्यादा है), तो निवेशकों को नुकसान होगा। मौजूदा तेजी के कारण निवेश के असली क्षेत्र पिछड़ सकते हैं। ये वे क्षेत्र हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की बुनियाद होते हैं। इनके रिटर्न तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इसीलिए लोग अभी इनमें निवेश करने से बच रहे हैं। इसका पैसा तुरंत लाभ देने वाली कंपनियों के खाते में जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। जैसे, यदि सुनहरे भविष्य को देखते हुए टेक्नोलॉजी कंपनियों में हम ज्यादा निवेश करते हैं, तो हमें बेशक रिटर्न ज्यादा मिले, लेकिन इससे रोजगार सृजन का परिदृश्य प्रभावित हो सकता है, यानी खतरा दोतरफा है- वास्तविक निवेश न होने से अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और दूसरा, रोजगार प्रभावित होगा। एक और बात, हमारे शेयर बाजार में कॉरपोरेट सेक्टर का प्रभुत्व है। ऐसे उद्योगपतियों की संख्या पांच से दस लाख के करीब है। मगर देश की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी महज 0.1 फीसदी है। साफ है, शेयर बाजार के चढ़ने से ज्यादा फायदा इसी वर्ग को होगा। यही अब तक होता रहा है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में खुदरा निवेशकों की संख्या ठीक-ठाक है। इसके कारण शेयर बाजार का फायदा वहां कई वर्गों में बंटता है। अपने यहां एक बड़ी आबादी शेयर बाजार के फायदे से वंचित रह जाती है। फिर, शेयर बाजार जब टूटता है, तो बड़े निवेशक जैसे-तैसे उसे सह जाते हैं, लेकिन कम पूंजी होने के कारण खुदरा निवेशकों को नुकसान अधिक होता है। हर्षद मेहता केस इसका बड़ा उदाहरण है। इन सबसे बचने के लिए सरकार को कुछ प्रयास करने चाहिए। मुमकिन हो, तो उसे छोटी अवधि वाले पूंजीगत लाभ के टैक्स बढ़ा देने चाहिए। इतना ही नहीं, शेयर बाजार में लेन-देन, यानी ट्रांजेक्शन पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए। इनसे भेड़चाल में होने वाली खरीद-बिक्री हतोत्साहित होगी। एकाध दिन में ही अच्छा-खासा रिटर्न पाने की उम्मीद में बड़ा निवेश करने वाले निवेशक भी अपने पांव पीछे खींचने को मजबूर होंगे। इससे न केवल सरकार का खजाना बढ़ेगा, बल्कि बुनियादी ढांचों के विकास पर वह कहीं ज्यादा रकम खर्च कर सकेगी। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि विदेशी बाजारों में कोई हलचल होते ही भारतीय शेयर बाजार की यह तेजी मंद पड़ सकती है। विदेशी निवेशकों के पीछे हटने की शुरुआत इसका एक बड़ा संकेत है। इस समय लिक्विडिटी अधिक होने की वजह से शेयर बाजार में लोग पैसे तो लगा रहे हैं, लेकिन जब उनके हाथ तंग होंगे, तो वे अपनी पूंजी निकालने से हिचकेंगे भी नहीं। ऐसी स्थिति में बाजार बिखरने लगेगा। यानी, आज का बुलबुला दीर्घावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नीति-नियंताओं को इसी पर ध्यान देना चाहिए।

प्रवीण कुमार सिंह

बाइडन की खोखली और दिशाहीन नीति के चलते अफगान मुद्दे पर यूएस की हो रही जगहंसाई

दुर्भाग्य से जैसे पाकिस्तान तालिबान के पीछे खड़ा है वैसे ही चीन भी। चीन की मंशा बेल्ट एंड रोड योजना अफगानिस्तान तक ले जाने की है। वह पैसे के दम पर तालिबान को साधने की कोशिश में है। यदि तालिबान पर पाकिस्तान के साथ चीन का प्रभाव बढ़ा तो मध्य एशिया में भारत के लिए चिंताजनक स्थिति बन सकती है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में योगदान देने और वहां बुनियादी ढांचे में करीब तीन अरब डालर खर्च करने वाला भारत तालिबान को लेकर तत्काल किसी पहल से बच रहा है। यह उचित भी है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में सरकार का गठन होना और उसकी रीति-नीति तय होना शेष है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कुछ समय पहले जब यह घोषणा की थी कि वह 31 अगस्त तक अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से हटा लेंगे तभी से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि अमेरिका तालिबान को नियंत्रित किए बिना वहां से निकल रहा है और इसके दुष्परिणाम अवश्य सामने आएंगे। तालिबान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा के उपरांत ही अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। हैरानी यह रही कि अफगान सेना ने शायद ही कहीं पर तालिबान का प्रतिरोध किया हो। ऐसे हालात में भी अमेरिका का आकलन यह था कि तालिबान के काबुल तक पहुंचने में करीब 90 दिन लग सकते हैं, लेकिन वे एक सप्ताह के अंदर ही वहां जा धमके। इसी के साथ अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी खुफिया तंत्र के आकलन की पोल खुल गई। तालिबान के काबुल पर कब्जे के साथ ही हजारों अफगानी नागरिक जिस तरह देश छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर जमा होने लगे और इसके कारण जैसे हालात पैदा हुए, वे दिल दहलाने वाले रहे। कई लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए हवाई जहाज के बाहर ही लटक गए और अपनी जान गंवा बैठे। कई माताएं अपने बच्चों को अमेरिकी सेनाओं को सौंपने लगीं कि उनकी जान बचा लो।

अमेरिका ने पिछले 20 वर्षों में करीब दो ट्रिलियन डालर अफगानिस्तान में खर्च किए। इनमें से करीब 80 प्रतिशत धन अमेरिकी सैनिकों और कंपनियों पर खर्च हुआ। शेष 20 प्रतिशत वहां के आधारभूत ढांचे के निर्माण में। आखिर इतना धन खर्च करने के बाद भी अमेरिका अफगान सेना को सक्षम क्यों नहीं बना सका? इसका यही जवाब है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में वही गलती की जो उसने वियतनाम, इराक, लीबिया आदि में की थी। अमेरिका ने जिस भी देश में अपनी

सेनाएं भेजकर वहां के हालात अपने हिसाब से नियंत्रित करने की कोशिश की, वहां वह नाकाम ही हुआ, क्योंकि उसने कभी भी संबंधित देश की सामाजिक संरचना और जमीनी हकीकत पर गौर नहीं किया।

अमेरिकी प्रशासन हमेशा इसी अहंकार में रहा कि अपने सैन्य बल के दम पर वह किसी भी देश में अपने पिट्ठू नेताओं को खड़ाकर स्थिरता ले आएगा। इतिहास गवाह है कि वह अपने इस मकसद में कभी सफल नहीं रहा। अमेरिकी प्रशासन अफगानिस्तान की चुनौतियों को समझने से इन्कार करता रहा। उसने यही समझा कि वह राष्ट्रपति अशरफ गनी को लोकतांत्रिक रूप से सशक्त करने के साथ अफगान सेना को मजबूत बना रहा है। यह समझ गलत साबित हुई। इसका जिम्मेदार वही है। उसने जब दोहा में तालिबान से समझौता किया तब गनी सरकार को उससे बाहर रखा। इससे गनी सरकार और अफगान सेना, दोनों का मनोबल गिरा। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका ने कई ऐसी गलतियां कीं जिनका उसे जवाब देना होगा। एक तो सैन्य वापसी का उसका फैसला सवालों के घेरे में है और दूसरे, उसे इसका भी जवाब देना होगा कि यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया कि अमेरिकी फौज के अत्याधुनिक हथियार और उपकरण तालिबान के हाथों में न लगने पाएं। तालिबान के हाथ लगे ये हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं।

अफगान सेना ने तालिबान के सामने जिस तरह हाथ खड़े किए, उससे स्पष्ट है कि वह एक खोखला सैन्य बल था। देश छोड़कर भागे अशरफ गनी ने सफाई दी कि उन्हें अपनी जान का भी खतरा था, क्योंकि इन्हीं तालिबान ने 25 साल पहले अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्ला को मारकर लैंपपोस्ट पर लटका दिया था। उनकी आशंका सही भी हो सकती है, लेकिन यह भी देखना होगा कि उन्होंने अमेरिका को अंधेरे में रखा और खुद अमेरिकी अधिकारी भी यह नहीं देख सके कि अफगान सेना किस हाल में है? अफगान सैनिकों को समय पर वेतन मिलना तो दूर रहा, वर्दी और जूते तक नहीं मिलते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी और अफगान अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण तीन लाख संख्या वाली अफगान सेना केवल कागजों पर खड़ी हुई हो?

अमेरिका से एक बड़ी भूल यह भी हुई कि उसने तालिबान की जड़ पर प्रहार नहीं किया। तालिबान की जड़ें पाकिस्तान में हैं। उनके काबुल में काबिज हो जाने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहा कि अब अफगानिस्तान गुलामी से मुक्त हो गया। पाकिस्तान तालिबान के जरिये अफगानिस्तान पर दबदबा बनाना चाहता है। यह बात अमेरिका भी जानता था, पर उसने पाकिस्तान को कभी दंडित नहीं किया। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से भाग कर पाकिस्तान में ही छिपा था। अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान की असलियत को भांपते हुए भी आंखें बंद किए रहा। उसने उसके प्रति आगाह करने वाली अमेरिकी थिंक टैंकों की रिपोर्टों की भी अनदेखी की।

भारत भी अमेरिका को पाकिस्तान के मंसूबों को लेकर आगाह करता रहा, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वह इसकी भी अनदेखी करता रहा कि पाकिस्तान किस तरह आतंकी संगठनों की शरणस्थली है। अफगानिस्तान का प्रकरण इसकी गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका की विदेश नीति खोखली भी है और दिशाहीन भी। आज अगर अमेरिका की जगहंसाई हो रही है और उस पर यह दोषारोपण हो रहा है कि उसने अफगानिस्तान को गर्त में धकेल दिया तो इसकी वजह उसकी पाकिस्तान नीति है। तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज तो हो गए, मगर उनके लिए शासन आसान नहीं। अफगानिस्तान में गरीबी पसरी है और अर्थव्यवस्था तंगहाल। तालिबान की आर्थिकी अफीम की खेती पर निर्भर है। अफगानिस्तान अफीम, हेरोइन आदि का सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिका नशे के इस कारोबार पर भी अंकुश नहीं लगा सका।

तालिबान चाहे जैसे दावे क्यों न करे, उसमें कोई बुनियादी बदलाव आता नहीं दिख रहा है। वह कुल मिलाकर एक आतंकी संगठन है। तालिबान ने महिलाओं को अधिकार देने और बदले की भावना से काम न करने का भरोसा दिलाने की जो कोशिश की थी वह 48 घंटे में ही दुनिया को धोखा देने का हथकंडा साबित हो गई। दुर्भाग्य से जैसे पाकिस्तान तालिबान के पीछे खड़ा है वैसे ही चीन भी। चीन की मंशा बेल्ट एंड रोड योजना अफगानिस्तान तक ले जाने की है। वह पैसे के दम पर तालिबान को साधने की कोशिश में है। यदि तालिबान पर पाकिस्तान के साथ चीन का प्रभाव बढ़ा तो मध्य एशिया में भारत के लिए चिंताजनक स्थिति बन सकती है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में योगदान देने और वहां बुनियादी ढांचे में करीब तीन अरब डालर खर्च करने वाला भारत तालिबान को लेकर तत्काल किसी पहल से बच रहा है। यह उचित भी है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में सरकार का गठन होना और उसकी रीति-नीति तय होना शेष है।

शेयर बाजार जुआघर नहीं, अर्थव्यवस्था की चाल को नापने का है आर्थिक बैरोमीटर

इस समय दुनियाभर के विकासशील देशों के शेयर बाजारों की तस्वीर में भारतीय शेयर बाजार की स्थिति शानदार दिखाई दे रही है। भारतीय शेयर बाजार का चमकीला परिदृश्य निवेशकों, उद्योग-कारोबार और सरकार, तीनों के लिए लाभप्रद है। पिछले वर्ष 23 मार्च, 2020 को जो बांबे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 25,981 अंकों के साथ ढलान पर दिखाई दिया था, वह पांच अगस्त, 2021 को 54,717.24 अंकों के स्तर को छूने में सफल रहा। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले चार महीनों यानी अप्रैल से जुलाई में शेयर बाजार के निवेशकों ने 31 लाख करोड़ रुपये की कमाई की है। इस समय शेयर बाजार में आइपीओ लाने की होड़ मची हुई है। आइपीओ में खुदरा निवेशकों की भागीदारी 25 फीसद बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष में 1.4 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते खुले हैं। देश में डीमैट खातों की संख्या 6.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यह बात महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में आई तेजी की वजह से दशक में पहली बार भारत की सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से ज्यादा हो गया है। इस लिहाज से बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात 100 फीसद को पार कर गया है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, हांगकांग, कनाडा, आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों में भी यह अनुपात 100 फीसद से अधिक है।

देश में शेयर बाजार के तेजी से आगे बढ़ने के कई कारण दिखाई दे रहे हैं। निवेशक यह देख रहे हैं कि कोरोना की चुनौतियों के बीच वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर आठ से नौ फीसद पहुंच सकती है। वहीं भारत समेत दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने बाजार में बड़ी मात्रा में पूंजी डाली है। ऐसे में इस समय ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से नीचे हैं। निवेशक यह भी देख रहे हैं कि करीब छह फीसद से अधिक के मुद्रा प्रसार के बीच फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) पर प्राप्त होने वाला लाभ शेयर बाजार के लाभ से कम हैं। अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंधों की संभावनाओं से निवेशकों की धारणा को बल मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत होने से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में ज्यादा पूंजी लगाने में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने वृद्धि दर और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर जो एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है, उससे भी शेयर बाजार को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

दरअसल वित्त मंत्री ने बजट में प्रत्यक्ष करों और जीएसटी में 22 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.8 फीसद तक विस्तारित करने में कोई संकोच नहीं किया है। बजट में सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ बीमा-बैंकिंग, विद्युत और कर सुधारों की डगर पर आगे बढ़ी है। इससे भी शेयर बाजार को गति मिली है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, विनिर्माण तथा सिर्वस सेक्टर को भारी प्रोत्साहन शेयर बाजार के लिए लाभप्रद है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने से इस क्षेत्र को नई पूंजी प्राप्त करने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। 20,000 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ ढांचागत क्षेत्र पर केंद्रित नए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआइ) की स्थापना अच्छा कदम है। टीडीएस नियम भी सरल बनाने की पहल की गई है।

बजट में कारपोरेट बांड बाजार की मदद के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचा तैयार करने की कोशिश की गई है। बिजली वितरण क्षेत्र को उबारने के लिए बजट में 3,00,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वित्त मंत्री ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के बोझ से दबे सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

सरकार ने आइडीबीआइ बैंक के अलावा दो अन्य सार्वजनिक बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है। बजट में लाभांश पर स्पष्टता सुनिश्चित की गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और निवेशक बाजार में धन लगाने के लिए आर्किषत हो रहे हैं। यद्यपि छोटे और ग्रामीण निवेशकों की दृष्टि से शेयर बाजार की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाना जरूरी है। लोगों को यह समझाया जाना होगा कि शेयर बाजार कोई जुआघर नहीं है। यह तो देश की अर्थव्यवस्था की चाल को नापने का एक र्आिथक बैरोमीटर है। निस्संदेह इस समय भारत में शेयर बाजार के तेजी से आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस तरह लंबे समय से सुस्त पड़ी हुई कंपनियों के शेयर की बिक्री कोविड-19 के बीच तेजी से बढ़ी है, उससे शेयर बाजार में जोखिम भी बढ़ गया है। इसका सबसे अधिक ध्यान रिटेल निवेशकों को रखना होगा।

ऐसे में शेयर बाजार में हर कदम फूंक-फूंककर रखना जरूरी है। शेयर बाजार की ऊंचाई के साथ-साथ छोटे निवेशकों के हितों और उनकी पूंजी की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। सरकार द्वारा शेयर और पूंजी बाजार को मजबूत बनाने की डगर पर आगे बढ़ने के लिए सेबी की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाना होगा। हम उम्मीद करें कि कोविड-19 से ध्वस्त देश के उद्योग-कारोबार सेक्टर को पुनर्जीवित करने में शेयर बाजार बहुत प्रभावी भूमिका निभाएगा। निवेशक शेयर बाजार का लाभ लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे।

अहम है यह आम राय

अफगानिस्तान के विषम हालात पर केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक अपने उद्देश्यों में सफल हुई कही जा सकती है। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही वहां से विचलित करने वाली तस्वीरें, वीडियो और खबरें आ रही हैं। ऐसे में आम लोगों के बीच ही नहीं तमाम राजनीतिक दलों के मन में भी यह सवाल उठना लाजिमी था कि आखिर हमारी सरकार इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देख रही है। अफगानिस्तान के साथ न केवल हमारा सदियों पुराना रिश्ता रहा है, बल्कि वहां हाल के वर्षों में हमने बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है। इसके अलावा वहां पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता आम तौर पर पूरी दुनिया और खास तौर पर दक्षिण एशिया की शांति के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकती है।

सर्वदलीय बैठक में सरकार ने साझा चिंता के इन तमाम बिंदुओं को संबोधित किया और जहां तक संभव था अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिलहाल भारत की पहली प्राथमिकता है वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपना यह अभियान जारी रखे हुए है। जहां तक अन्य पहलुओं की बात है तो भारत सरकार तमाम मित्र देशों से संपर्क में है, वहां शांति और व्यवस्था स्थापित करने के साथ ही वैकल्पिक सरकार गठन की कोशिशों पर भी बात हो रही है, लेकिन इस मामले में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। ऐसे मामले जल्दबाजी में तय नहीं होते।

विदेश मंत्री ने यह कहने में भी कोई संकोच नहीं किया कि तालिबान दोहा में किए गए अपने वादों पर कायम नहीं रहे। वहां तय हुआ था कि काबुल में अफगान समाज के हर तबके की नुमाइंदगी वाली सरकार के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाएगा। फिर भी, उन्होंने यह साफ किया कि सरकार अफगानिस्तान में हरेक स्टेक होल्डर से संपर्क बनाने और संवाद प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां तक रुख तय करने की बात है तो फिलहाल तो %वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही सबसे उपयुक्त है। इसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का सबूत ही कहा जाएगा कि घरेलू राजनीति में कई मसलों पर एक-दूसरे का तीव्र विरोध कर रहे तमाम दल अफगानिस्तान के सवाल पर सरकार के सुर में सुर मिलाए नजर आए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम दलों की भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वह पूरे देश की समस्या है। कहने की जरूरत नहीं कि सही मौके पर उभर आने वाली ऐसी राजनीतिक सर्वसम्मति बेहद अहम होती है। यह जहां विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार को ताकत देती है, वहीं देश में लोकतंत्र की जड़ को मजबूत बनाती है।

अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति से जम्मू-कश्मीर में विकास का सपना हो रहा साकार

अच्छी बात यह है कि पहले इस आयोग का बहिष्कार करने वाले नेशनल कांफ्रेंस जैसे दल भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर इसे समग्र और समावेशी बना रहे हैं। 'एक विधान, एक निशान, सबको समता और सम्मान' न सिर्फ जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में देश के नीति-नियंताओं का पाथेय बने, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में इसे अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। गुलाम कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं है। पाकिस्तानी फौज द्वारा वहां के लोगों पर ढाए जा रहे जुल्मो-सितम से निकलने वाली करुण-पुकार को लंबे समय तक अनसुना नहीं किया जा सकता है।

आजादी से लेकर पांच अगस्त, 2019 तक जम्मू-कश्मीर प्रदेश का अधिसंख्य समाज कश्मीर के नेतृत्व वाली सरकार की कश्मीर-केंद्रित भेदभावपूर्ण नीति का शिकार रहा था। यह भेदभाव विकास योजनाओं से लेकर लोकतांत्रिक भागीदारी तक और एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों और बहन-बेटियों के न्यायसंगत अधिकारों की अवहेलना तक व्याप्त था। पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा 35ए की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर के वर्षों से उपेक्षित वंचित वर्गों को न्याय देने की परियोजना प्रारंभ हुई। इससे प्रदेश में अनेक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई है। इससे जम्मू-कश्मीर की एकात्मता और विकास का सपना साकार हो सका है।

पिछले दो वर्षों की अल्पावधि में ही जम्मू-कश्मीर में जमीनी बदलाव नजर आने लगा है। कुछ काम हो गया है और बहुत काम होना बाकी है। 28 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद यहां पिछले साल से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह लागू हो गई है। स्थानीय निकायों को वे सभी अधिकार और संसाधन मिल गए हैं, जो देशभर में मिलते हैं। जम्मू-कश्मीर में एसटी वर्ग (गुज्जर बक्करवाल, गद्दी, सिप्पी आदि) को राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिला है, जिससे इस वर्ग के विकास के रास्ते खुले हैं। अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देकर सामाजिक-न्याय सुनिश्चित किया गया है। संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर का यही सपना था कि भारत में समतामूलक और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। कहीं भी जाति-धर्म, क्षेत्र और लिंग आदि के आधार पर

कोई भेदभाव नहीं हो। यह संतोष की बात है कि कुछ देर से सही, उनका यह स्वप्न देश के अन्य भागों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी साकार हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में अधिकारों से वंचित बहनों-बेटियों को न्याय मिला है। इससे पहले जिनका विवाह प्रदेश से बाहर हो जाता था, उन्हें उनके जन्मजात अधिकारों तक से वंचित कर दिया जाता था। स्वाधीन भारत में लैंगिक भेदभाव का यह शर्मनाक उदाहरण था, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं था।

हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय 'एक व्यक्ति-एक मत' का प्रविधान करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पहले महिलाओं को मताधिकार देकर प्रगतिशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था का परिचय दिया था। किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ही उनके मार्गदर्शक सिद्धांत थे। जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद 370 और धारा 35ए के तहत मिले अस्थायी विशेषाधिकारों की आड़ में इन सिद्धांतों की अवहेलना करता आ रहा था। अब वहां भारत का संविधान पूरी तरह लागू होने से आमूलचूल सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का राह खुल गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता और भेदभाव किसी भी समाज के लिए अभिशाप हैं। जम्मू-कश्मीर अब इस अभिशाप-मुक्ति की दिशा में बढ़ चला है। इसी के चलते प्रदेश में बसे हुए लाखों दलितों विशेषकर वाल्मीकि समाज, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखा और गुलाम कश्मीर के विस्थापितों को सम्मान, समान अवसर और मतदान जैसे मूल अधिकार और सुविधाएं मिली हैं।

इनके अलावा नई औद्योगिक नीति लागू होने और निवेशक सम्मेलनों के आयोजन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई है। नई भाषा नीति लागू करके डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को राजभाषा (शासन-प्रशासन की भाषा) का दर्जा देकर स्थानीय लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी हुआ है। अभी तक आतंकवाद और भेदभाव के शिकार रहे पर्यटन उद्योग को पुनः विकसित किया जा रहा है। इस कड़ी में श्री वेंकटेश्वर भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण, देविका नदी और शिवखोड़ी गुफा जैसे पवित्र-स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है।

आतंकवादियों के पनाहगार बने दर्जनों सरकारी कर्मी बर्खास्त किए जा चुके हैं और सैकड़ों के खिलाफ जांच चल रही है। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों और अलगाववादियों की नकेल कसने और हवाला फंडिंग रुकने से राष्ट्रविरोधी हिंसक गतिविधियों में निर्णायक गिरावट आई है। पांच अगस्त, 2019 के बाद से प्रदेश में आतंकवादी वारदातें 59 प्रतिशत तक कम हुई हैं। जम्मू-कश्मीरवासियों को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के अंतर्गत कश्मीरी विस्थापितों के लिए रोजगार और आवास की व्यवस्था हो रही है। ई-फाइलिंग के जरिये अर्धवार्षिक 'दरबार-मूव' की खर्चीली कवायद को समाप्त किया गया है। विभिन्न कार्यों के समयबद्ध निपटारे और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिटिजंस चार्टर लागू किया गया है। इससे निष्क्रिय और टालू सरकारी कर्मी हरकत में आ रहे हैं। रोशनी एक्ट और शस्त्र लाइसेंस घोटाले में धर-पकड़ हो रही है।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करके उन्हें संतुलित और न्यायसंगत बनाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पहले इस आयोग का बहिष्कार करने वाले नेशनल कांफ्रेंस जैसे दल भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर इसे समग्र और समावेशी बना रहे हैं। 'एक विधान, एक निशान, सबको समता और सम्मान' न सिर्फ जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में देश के नीति-नियंताओं का पाथेय बने, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में इसे अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। गुलाम कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं है। पाकिस्तानी फौज द्वारा वहां के लोगों पर ढाए जा रहे जुल्मो-सितम से निकलने वाली करुण-पुकार को लंबे समय तक अनसुना नहीं किया जा सकता है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

फिर चर्चा में आया साक्षी महाराज का बयान, बोले- मैं मुस्लिम नहीं, वंदेमातरम न गाने वालों का विरोधी

उन्नाव । अक्सर अपने बयानों से विवाद और सुर्खियों में रहने वाले सांसद साक्षी महाराज ने अब मुस्लिमों के लिए बड़ी बात कही है। उन्होंने हितषी बनने वाले विपक्षियों को घेरते हुए कहा है कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं। पत्रकारों को दिए बयान में सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि मैं मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय न बोलने वालों और वंदेमातरम न गाने वाले लोगों का विरोधी हूं। उन्होंने भाजपा की सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को गिनाया और गरीबों की हतैषी बताया।

उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, इतना ही नहीं वह अपनी पार्टी के बारे में भी बयान देने से नहीं चूकते हैं। पहले भी वह पार्टी को लेकर बयान देकर कई बार चर्चा में रहे और अब मुस्लिमों के लिए बयान देकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। एक संक्षिप्त पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम विरोधी नही हूं, अब्दुल कलाम, असफाक उल्लाह खान आदि लोग भी मुसलमान थे और वो देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे लोगों को मैं आज भी नमन और सलाम करता हूं। मैं उन लोगों का विरोध करता हूं जो हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय बोलने व वंदे मातरम का गान करने से परहेज करते हैं तथा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। अब यह नहीं चलेगा भारत में वही रहेगा जो भारत माता की जय बोलेगा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पूर्व की सरकारों में बड़े-बड़े गोदामों में अनाज सड़ जाता था। लोग भूख से मर जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि अब अन्न गोदामों में नहीं सड़ने देंगे और उसे गरीबों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सभी को अन्न, आवास, नल और नल में जल देने संकल्प पूरा कर रहे हैं। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इससे वह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं।

नाती के बर्थ-डे पर दिल्ली में रोमांटिक अंदाज में दिखे लालू-राबड़ी

पटना। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों बीमार हैं। चेहरे पर उम्र की थकान भी साफ नजर आने लगी है, लेकिन दिल अभी जवां है। जनता से संपर्क बनाना हो या परिवार व पार्टी की एकजुटता की बात हो, उनकी काबिलियत कमाल की रही है। मुश्किल दौर में भी परेशानी को छिपा लेने में महरत हासिल कर चुके लालू लंबे समय बाद पत्नी राबड़ी देवी संग एक पेयर तस्वीर में नजर आए हैं। इसमें एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखे दोनों के मुस्कुराते चेहरे का रोमांटिक अंदाज दिख रहा है। तस्वीर बेटी मीसा भारती के बेटे अधिराज के पांचवे बर्थ-डे का है। सोमवार को मीसा भारती के पांच साल के बेटे अधिराज का जन्मदिन था। लालू प्रसाद यादव इन दिनों मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर हैं। पत्नी राबड़ी देवी भी वहीं साथ में हैं। नाती के जन्मदिन के अवसर पर लालू व राबड़ी खुश नजर आए। हाल के दिनों में लालू थके नजर आए थे, लेकिन सोमवार की तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चेहरे पर वहीं पुरानी हंसी दिख रही है।

नाती अधिराज के बर्थ-डे के अवसर पर लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी ने पेयर तस्वीर भी खिंचवाई। दोनों की ऐसी तस्वीर लंबे समय बाद दिखी है। तस्वीर में दोनों एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखे व खुश नजर आ रहे हैं। बहुत पहले लालू प्रसाद यादव की राबड़ी देवी को गुलाब देती एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। ताजा तस्वीर ने उस तस्वीर की भी याद दिला दी है। इसी संदर्भ में यी भी जान लीजिए कि एक बार मीडिया ने जब राबड़ी देवी के बारे में पूछा था तो लालू ने कहा था कि राबड़ी देवी का तो नाम ही राबड़ी है।

सदानंद सिंह के साथ बिहार कांग्रेस के एक युग का अंत

पटना । बिहार कांग्रेस के वरीय नेता सदानंद सिंह का बुधवार की सुबह पटना के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे लंबे समय से लिवर सिरोसिस की बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन के साथ बिहार में कांग्रेस के एक युग का अंत हो गया है। उनके निधन पर शोक संवदनाओं का तांता लग गया है। शोक प्रकट करने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। सदानंद सिंह के पार्थिव शरीर को इस वक्त बिहार विधानसभा लाया गया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद उन्हें पटना स्थित आवास पर ले जाएगा। सदानंद सिंह कांग्रेस ही नहीं, बिहार के सबसे बुजुर्ग व बड़े नेताओं में शामिल रहे। वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। वे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। उन्होंनेभागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट का नौ बार प्रतिनिधित्व किया।

आठ जुलाई से खराब थी तबीयत- सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश के अनुसार उनके पिता की तबीयत आठ जुलाई से खराब थी। पहले उन्हें दिल्ली में डाक्टरों की निगरानी में दो सप्ताह तक रखा गया। फिर, पटना लाया गया। अगस्त में फिर तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के दानापुर के क्यूरिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पुलिस कस्टडी में युवक ने मुखिया पद के लिए किया नामांकन

बेलागंज (गया)। मंगलवार को दोपहर बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित नामांकन केंद्र पर अफरातफरी का माहौल बन गया। जब हाथ में हथकड़ी लगे एक युवक को कुछ पुलिस बल अपने साथ लाए। उसने पुलिस अभिरक्षा में मुखिया पद पर अपना नामांकन दाखिल किया। बेलागंज व मेन थाना के विभिन्न कांडों का नामजद आरोपित कौशल शर्मा को पुलिस ने एक पखवारा पहले गिरफ्तार की थी, जो अभी न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार गया में बंद है।मंगलवार को न्यायालय के निर्देश के पर पुलिस अभिरक्षा में वह कोरमथु पंचायत के मुखिया पद के लिए नामांकन करने प्रखंड मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके समर्थकों का हुजूम जुटा हुआ था।

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के अलीगढ़ आगमन से पहले परखी तैयारियां, अधिकारियों को दिए निर्देश

अलीगढ़ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित?यनाथ दोपहर हेलीकाप्टर से अलीगढ़ लोधा पहुंच गए। मुख्यमंत्री 14 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद वे सर्किट हाउस में अलीगढ़ व आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों और मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर जाकर व्यवस्थाएं देखी। दिनभर विधायक व सांसदों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।

एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ उनके ड्यूटी प्वाइंट तय किए गए हैं। वाहनों की पार्किंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में सांसद सतीश गौतम, हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर, विधायक रवेंद्र पाल सिंह, शहर विधायक संजीव राजा, खैर विधायक अनूप प्रधान, इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी, मंडलायुक्त गौरव दयाल, डीआइजी दीपक कुमार, सीडीओ अंकित खंडेलवाल, एडीएम प्रशासन डीपी पाल, एसपी श्वेताभ पांडे, शुभम पटेल, सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह, एसडीएम खैर अर्जनि कुमार सिंह, एसडीएम कोल कुंवर बहादुर सिंह आदि के मौजूद रहने की उम्मीद है। ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 14 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लोधा ब्लाक क्षेत्र में आयोजित सभा में करीब एक लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। अलीगढ़, एटा, कासगंज व हाथरस, आगरा, मथुरा, मैनपुरी व फिरोजाबाद के लोग भी इसमें शामिल होंगे। सभी के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय व डिफेंस कारिडोर सहित करीब 250 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। वहीं, प्रभारी मंत्री सुरेश राणा भी अलीगढ़ पहुंच गए हैं। मंगलवार को कमिश्नर गौरव दयाल व डीएम ने जनप्रतिनिधि व पुलिस-प्रशासनिक अफसरों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की।

सीएम योगी आदित्यनाथ लोधा में कार्यक्रम स्थल पर प्रोजेक्टर पर यूनिवर्सिटी को लेकर 14 सितम्बर को पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां परख रहे हैं। अलीगढ़ आगमन पर सीएम योगी ने लोधा में यूनिवर्सिटी के लिए तय की गई जमीन का निरीक्षण किया। यहीं चौदह सितंबर को पीएम की सभा होनी है। इसमें एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इसे ध्यान में रखकर ही तैयारियां की जा रही हैं। सभा के लिए विशाल पंडाल बनाया जाएगा। अलीगढ़ के अलावा आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा सहित अन्य जिलों के लोग भी सभा में शामिल होंगे। सभा के दौरान ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, डिफेंस कारिडोर सहित अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण होना है। हालांकि, धनीपुर एयरपोर्ट के लोकार्पण की भी संभावना थी, लेकिन अभी यह पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इसका प्रस्ताव पीएम तक भिजवाने की बात सांसद ने पिछले दिनों कही थी।

यूपी में दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की फिर होगी छंटनी, स्क्रीनिंग शुरू करने का आदेश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की फिर छटनी शुरू होने जा रही है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों में नकारा पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग किये जाने का निर्देश दिया है। 50 वर्ष व उससे अधिक आयु के दागी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने के लिए स्क्रीनिंग शुरू करने का आदेश दिया गया है। योगी सरकार की जीरो टालरेंस की नीति के तहत पहले भी दागी पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। बीते दिनों तीन आइपीएस अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। 30 नवंबर तक स्क्रीनिंग का ब्योरा डीजीपी मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और पुलिस कमिश्नरों भेजे गए पत्र में 50 साल या इससे ऊपर की उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाई समय और नियम के मुताबिक कराने को कहा गया है। इस पत्र में 26 अक्टूबर, 1985 से लेकर छह जुलाई, 2017 तक के कई शासनादेशों का हवाला भी दिया गया है और पहले की तरह कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

पत्र में साफ लिखा है कि 30 मार्च, 2021 को 50 साल या इससे अधिक की उम्र के पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाई कराई जाए। स्क्रीनिंग कमेटी में नान गजेटेड पुलिसकर्मियों को नियुक्त करने वाले अधिकारियों को रखने की बात भी कही गई है। दागी, भ्रष्ट, अयोग्य और अनुशासन का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करा कर 30 नवंबर, 2021 तक एडीजी स्थापना के दफ्तर को सूचित करने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत इसमें लिप्त अफसरों और कर्मचारियों की स्क्रीनिग के आदेश दिए हैं। अब तक तीन आइपीएस अधिकारी समेत चार सौ से ज्यादा पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दिया जा चुका है। आइपीएस अमिताभ ठाकुर, राकेश शंकर और राजेश कृष्णा इसी नीति के तहत रिटायर कर दिए गए थे।

दरअसल, पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन और योग्यता के लिए हर साल उनकी एसीआर बनाई जाती है। इसी के आधार पर ही छंटनी की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की भर्ती नियमावली के नियम 56 ग के तहत कर्मचारियों की उपयुक्तता को उसका नियुक्ति अधिकारी तय करता है और एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर अनुपयुक्त और अयोग्य कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति किया जाता है।

कोलकाता के भबनीपुर में पश्चिम बंगाल उपचुनाव के प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता दीवार पर अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह पेंट करते हुए।

प्रियंका वाड्रा 10 सितंबर को आएंगी लखनऊ, मिशन 2022 की तैयारियों को देंगी धार

लखनऊ । कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा 10 और 11 सितंबर को लखनऊ में होंगी। दो दिवसीय प्रवास के दौरान वह पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगी। संगठनात्मक समीक्षा के साथ प्रियंका चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए पार्टी की राज्य चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ बैठकें भी करेंगी। इससे पहले प्रियंका तीन दिवसीय प्रवास पर बीती 16 जुलाई को लखनऊ आयी थीं।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव में जीत के सूत्र तलाशने में जुट गए हैं। ऐसे में प्रियंका कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के साथ उन्हें गति देने की कोशिश करेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों का प्रशिक्षण देने के लिए कांग्रेस के प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम के जरिये वह कई जिलों के पार्टी पदाधिकारियों से रूबरू होने के साथ उनसे फीडबैक भी ले चुकी हैं।

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा के लखनऊ दौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनके आगमन के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की है।लखनऊ दौरे के दौरान वह विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेंगी। साथ ही साथ संगठन के विभिन्न नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। अपने दौरे के दौरान प्रियंका गांधी संगठन की समीक्षा भी करेंगी। इस दौरे में वह पार्टी की राज्य चुनाव समिति और सलाहकार समिति के अलावा अन्य समितियों के साथ भी बैठकें करेंगी।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी कर सकती है। प्रियंका वाड्रा इनमें से कुछ प्रत्याशियों से सीधे फोन पर बात भी कर रही हैं। उन्होंने इन सभी संभावित प्रत्याशियों से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी तैयारियां तेज करें, मजबूती से लड़ें और जीत कर आएं। पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करें।

यूपी पुलिस ने 800 अपराधियों को किया चिह्नित, अब तक ढाई अरब की अवैध संपत्ति जब्त

लखनऊ । कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टालरेंस की नीति का असर धरातल पर भी दिख रहा है। पुलिस ने जिले स्तर पर भी 800 आपराधियों को चिह्नित किया है। अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। पुलिस कुर्की से लेकर संपत्ति तक जब्त कर बदमाशों की कमर तोड़ रही है। ऐसे करीब ढाई अरब रुपये की अवैध संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जता दी थी कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। वे जेल में रहेंगे या प्रदेश के बाहर। प्रदेश स्तर पर बड़े माफिया पर शिकंजा कसते हुए अब जिले स्तर पर भी बड़े व आदतन अपराधियों को चिह्नित किया गया है।

यूपी पुलिस के अनुसार जिले स्तर पर जुलाई माह तक करीब 800 आपराधिक माफिया को चिह्नित किया गया है। आठ हजार से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर 668 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में तीन आपराधिक माफिया को मार भी गिराया है। 12 आरोपियों की कुर्की करते हुए 25 आरोपियों पर रासुका लगाया गया है। 567 आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने जिले स्तर पर कानून व्यवस्था में रोड़ा बन रहे 233 आपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत

कार्रवाई की है और 11 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं।

इसके अलावा ऐसे 382 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट भी खोली गई है और 274 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सूक्ष्म स्तर पर ही सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि कानून का खौफ हर किसी में हो।

ये हैं प्रदेश के 25 बड़े माफिया = गाजीपुर जिले के युसूफपुर मोहम्दाबाद निवासी मुख्तार अंसारी, प्रयागराज जिले के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र निवासी अतीक अहमद, वाराणसी जिले के चौबेपुर निवासी बृजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, लखनऊ जिले के हसनगंज निवासी ओमप्रकाश उर्फ बब्लू श्रीवास्तव, बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र निवासी मुनीर, अंबेडकरनगर जिले के हंसवार थानाक्षेत्र निवासी खान मुबारक, गाजियाबाद जिले के लोनी निवासी अमित कसाना, शामली जिले के आदर्श मंडी निवासी आकाश जाट, मेरठ जिले के सरूरपुर निवासी उधम सिंह, मेरठ जिले के सरूरपुर निवासी योगेश भदौड़ा, बागपत जिले के बड़ौत निवासी अजीत उर्फ हप्पू, मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुर निवासी सुशील उर्फ मूंछ, मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली निवासी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, गौतमबुद्धनगर जिले के कासना निवासी सुन्दर भाटी उर्फ नेताजी, गौतमबुद्धनगर जिले के कासना निवासी अनिल भाटी, गौतमबुद्धनगर जिले के बादलपुर निवासी अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर, गौतमबुद्धनगर जिले के दनकौर निवासी सिंघराज भाटी, गौतमबुद्धनगर जिले के जारचा निवासी अंकित गुर्जर, वाराणसी जिले के कोतवाली निवासी सुभाष सिंह ठाकुर, आजमगढ़ जिले के जीयनपुर निवासी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद उमेश राय उर्फ गौरा राय, गाजीपुर जिले के सैदपुर निवासी त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, लखनऊ जिले के कैंट निवासी मो. सलीम, लखनऊ जिले के कैंट निवासी मो. सोहराब और लखनऊ जिले के कैंट निवासी मो. रुस्तम हैं।

झलकारी बाई अस्पताल में हुई एक्सट्रीम प्री मेच्योर डिलीवरी, तीन माह बाद स्वस्थ्य होकर घर पहुंचा शिशु

लखनऊ । करीब तीन महीने के संघर्ष के बाद जब अपनी पहली संतान को गोद में लिया तो सीतापुर के दंपती की आंखें नम हो गईं। चैन से लेटे अपने स्वस्थ बेटे को देख दंपती ने हाथ जोड़कर डाक्टरों को धन्यवाद कहा। जन्म के बाद पहली बार बेटे को घर ले जाने की खुशी को दंपती शब्द नहीं दे पा रहे थे। झलकारी बाई महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डा रंजना खरे के अनुसार महीने में आठ-दस प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। अस्पताल में एनआइसीयू की व्यवस्था नहीं है, फिर भी सीमित संसाधनों के बीच बेहतर उपचार दिया जा रहा। पहली बार जन्म के बाद कोई बच्चा इतने लंबे समय तक अस्पताल में रहा। इस केस में डाक्टरों के साथ ही मां की मेहनत ने भी बच्चे को स्वस्थ होने में मदद की।

सुषमा को मां बनने का सुखद अहसास तो जून में हुआ पर इसी के साथ दंपती के संघर्ष का सिलसिला भी शुरू हो गया था। 28 हफ्तों की एक्सट्रीम प्री मेच्योर डिलीवरी के साथ ही बच्चा बेहद कम वजन (930 ग्राम) का था। झलकारी बाई महिला अस्पताल के डाक्टरों की टीम ने सीमित संसाधनों के बीच स्पेशल न्यूबार्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में ही बच्चे का उपचार किया और तीन महीने बाद बच्चे का वजन एक किलो से ज्यादा होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया।

यह सुषमा की पहली डिलीवरी थी। डिलीवरी समय से कुछ हफ्तों पहले ही रक्तस्राव होने के कारण 14 जून को सुषमा को झलकारी बाई महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सफल डिलीवरी भी हुई, पर बच्चा बेहद कम वजन का था। चिकित्सकों ने दंपती को बताया कि अस्पताल में सिर्फ एसएनसीयू होने के कारण वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, पर दंपती ने कहा कि वह उपलब्ध सुविधाओं में ही बच्चे का उपचार कराना चाहते हैं। डा पीके मिश्रा, डा सुरभि, डा विभा और डा सोनल की टीम बच्चे के उपचार में लगी।

बसपा से फिर मिले ब्राह्मण तो बदल जाएंगे सियासी समीकरण

लखनऊ । पिछले चुनावी दृश्य लहर से बदलते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय दांव से बाजी जीतते रहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भरोसा इसी सूत्र पर अब भी टिका है। निस्संदेह जाति की गोटें बिठाने में भारतीय जनता पार्टी के भी रणनीतिकार पीछे नहीं रहे, लेकिन बसपा व सपा का बहुत सधा गणित है। अपने-अपने जातिगत वोट बैंक के साथ मुस्लिम मत में हिस्सेदारी बराबरी के लिए है तो ब्राह्मणों के बोनस वोट से यह समीकरण बदल देना चाहते हैं। दलित-मुस्लिम-ब्राह्मण गठजोड़ से 2007 में सत्ता हासिल कर चुकीं बसपा सुप्रीमो मायावती खास तौर पर सोशल इंजीनियरिंग का दांव पूरी ताकत से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चलना चाहती हैं।

दरअसल, वर्ष 2012 में सत्ता गंवाने के बाद से अब तक हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा का जनाधार खिसकता ही रहा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। भाजपा के बढ़ते प्रभाव से पार्टी की घटती ताकत का ही नतीजा रहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी तक से गठबंधन करने में गुरेज नहीं किया। गठबंधन से पार्टी को दस लोकसभा सीटें तो मिल गईं, लेकिन पार्टी की स्थिति सुधरती नहीं दिखी। ऐसे में मायावती ने गठबंधन तोड़ अकेले ही विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया।

चूंकि वर्ष 2007 में दलितों के साथ ही बड़े पैमाने पर मुस्लिम और ब्राह्मण समाज को जोड़ने से पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही थी, इसलिए बसपा प्रमुख एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता हासिल करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। हालांकि, डेढ़ दशक में सूबे की राजनीति में बड़े बदलाव हो गए हैं। पहले हासिये पर रही भाजपा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण सहित पिछड़े व दलितों के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही जिससे भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ता ही रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में तो भाजपा अपने सहयोगियों के साथ रिकार्ड 325 सीटें जीतने में कामयाब रही।

पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के भाजपा से नाराज होने की चर्चा से समाज के वोट बैंक पर सपा के साथ ही बसपा की फिर से नजर है। वैसे तो भाजपा, ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करने के लिए तमाम जतन कर रही है लेकिन फिलहाल उसे पहले जैसा ब्राह्मणों का साथ मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सपा व बसपा ब्राह्मण समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए सम्मेलनों के साथ ही परशुराम की मूर्ति भी लगवा रही है।

मायावती और पार्टी महासचिव सतीश मिश्र को लगता है ब्राह्मण तो बसपा के साथ ही आएगा। वैसे तो अभी यही लगता है मुस्लिम समाज सपा के साथ रहेगा, लेकिन बसपा, मुस्लिम समाज को अबकी बार कहीं ज्यादा टिकट देने की तैयारी में हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज भी अगर बसपा से जुड़ता है तो उसके लिए सत्ता की राह आसान हो सकती है। हालांकि, जिस तरह से मुस्लिम वोटबैंक को लेकर छोटे दल भी सक्रिय होते दिख रहे हैं, उससे मुस्लिम मत बंट सकते हैं जिसका सीधा फायदा पूर्व की भांति भाजपा को मिलना तय है।

14 फीसद ब्राह्मणों का 103 सीटों पर प्रभाव = उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का सदैव वर्चस्व रहा है। राज्य की कुल आबादी में लगभग 14 फीसद हिस्सेदारी ब्राह्मण समाज की मानी जाती है। 403 विधानसभा सीटों में से 103 पर ब्राह्मण समाज का प्रभाव कहा जाता है। इनमें भी 47 सीटें तो ऐसी हैं, जिन पर 25 फीसद से भी ज्यादा ब्राह्मण समाज का वोट है। लखनऊ, वाराणसी, चंदौली, बहराइच, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, शाहजहांपुर, सीतापुर, कानपुर, सुलतानपुर, भदोही, जौनपुर, मीरजापुर, प्रयागराज, अंबेडकरनगर, गोंडा, बलरामपुर, संत कबीरनगर, महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, श्रावस्ती आदि जिलों की ज्यादातर सीटें ब्राह्मण बहल हैं।

बाढ़ शरणालय में दुश्वारियों के बीच दिन काट रहे पीड़ित, सुविधा के नाम पर मिली केवल छत

गोरखपुर । खाने के पैकेट से पूड़ियां निकालकर सुनीता दोनों हाथों से तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। मशक्कत के बाद भी वह पूड़ी नहीं तोड़ सकीं। दरअसल, सुनीता ऐसा करके बाढ़ शरणालय में प्रशासन की ओर से मुहैया करायी जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की हकीकत बताना चाहती थीं। सदर तहसील प्रशासन की ओर से महानगर के लालडिग्गी में बनाए गए बाढ़ शरणालय में सुनीता के साथ कई बाढ़ पीड़ित अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। घर में पानी भर जाने के कारण इन्हें रेस्क्यू कर यहां लाया गया है। सुविधा के नाम पर इन्हें केवल छत ही मिली है। वे दुश्वारियों के बीच जैसे-तैसे अपना जीवन काट रहे हैं।

शहर में बने बाढ़ शरणालय में सुविधाओं की पड़ताल करने के लिए सोमवार को दैनिक जागरण की टीम बाल विहार स्कूल पहुंची। यहां करीब 200 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को रखा गया है। स्कूल के बड़े-बड़े कमरों में बाढ़ पीड़ित अलग-अलग अपने परिवार के साथ समय बिताते नजर आए। कई परिवारों ने खाना बनाने की व्यवस्था भी रखी है। बाढ़ पीड़ित किरन का कहना है कि हम वास्तविक बाढ़ पीड़ित हैं। घर में राशन है लेकिन उसे लाने नहीं जा सकते। प्रशासन की ओर से राशन नहीं मिला है, बाहर से खरीदते हैं तब बनाकर खाते हैं।

बाढ़ पीड़ित सुनीता ने बताया कि एक समय तहरी और दूसरे समय छोटी-छोटी चार-पांच पूड़ियां ही पैकेट में होती है। मोटे चावल से बनी तहरी में आलू ढूंढने पड़ते हैं, मिले भी तो छिलके वाले। पूड़ियां इतनी कड़ी होती हैं कि दांतों से काटना मुश्किल होता है, सब्जी भी बहुत कम होती है। एक व्यक्ति को दो पैकेट मिले, तब जाकर पेट भरेगा। खाने के साथ ही यहां रह रहे बाढ़ पीड़ित गर्मी से भी परेशान हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी पंखे नहीं बन रहे।

इलाज के लिए दिल्ली जाने वाले अब पुराने मप्र भवन में ठहर सकेंगे

प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री चौहान की नई सौगात

भोपाल (एजेंसी)। मप्र के निवासियों के लिए अच्छी खबर है, अब इलाज के लिए दिल्ली जाने के बाद ठहरने की जगह की चिंता नहीं करना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेशवासियों को नई सौगात देते हुए दिल्ली में स्थित पुराने मध्यप्रदेश भवन को दिल्ली इलाज करवाने जाने वाले मारीजों और उनके परिजनों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुराने मध्यप्रदेश भवन का भी उपयोग दिल्ली में मप्र से इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजन के लिए इसे आरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उन्हें दिल्ली में इलाज के दौरान रुकने की कोई समस्या हो। गौरतलब है कि दिल्ली में नवीन मध्यप्रदेश भवन का निर्माण हो रहा है। नए भवन के निर्माण के बाद पुराने भवन क्या किया जाएगा, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि पुराने मप्र भवन में प्रदेश से दिल्ली आने वाले मरीज और परिजनों के ठहरने के उपयोग में ही लाया जाएगा।

सीएम ने किया नए मध्यप्रदेश भवन का अवलोकन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान बुधवार सुबह निर्माणाधीन नवीन मध्यप्रदेश भवन का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि नए भवन में राज्य के वैभव के दिग्दर्शन के प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ मध्यप्रदेश के जीवन मूल्यों, परम्पराओं, आस्थाओं, स्थापत्य कला, प्राकृतिक सुदंरता और महापुरुषों के आदर्शों की जानकारी मिलनी चाहिए।

नए भवन में दिखेगी मप्र के वैभव की झलक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश की परंपराओं और आस्थाओं को समाहित करते हुए महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, अमरकंटक, मितावली मंदिर, संदीपनि आश्रम और ओरछा के राम राजा मंदिर के साथ सांची, खजुराहो, असीरगढ़ और मांडू की स्थापत्य कला का किसी न किसी रूप में नवीन भवन में समावेश होना चाहिए। रघुनाथ शाह, शंकरशाह, टंट्याभील, भीमा नायक और रानी लक्ष्मी बाई जैसे प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों के आदर्शों की झलक भी नए भवन में दिखनी चाहिए। भवन की लेंडस्केपिंग में प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय कला सम्मिलित होनी चाहिए।

हो सकेंगी शासकीय बैठकें और बिजनेस मीट जैसे कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नए भवन में ऐसी व्यवस्थाएं हो, जिसमें शासकीय बैठकें और बिजनेस मीट जैसे कार्यक्रम किए जा सके। इन कार्यक्रमों के लिए अलग से किराए के स्थान की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि भवन में एक ओर मध्यप्रदेश की संस्कृति की झलक और दूसरी ओर शासकीय कार्यों को संचालित करने की सुगमता का मेल हो। एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को निर्माणाधीन मध्यप्रदेश भवन की कार्य प्रगति से अवगत कराते हुए ड्राइंग के माध्यम से प्रस्तुति दी और मुख्यमंत्री से आवश्यक निर्देश प्राप्त किए। आवासीय आयुक्त, अपर आवासीय आयुक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लघु वनोपज संग्रहण करने छह जिलों के लिए बना एक्शन प्लान : शाह

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने बताया है कि प्रदेश में 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए छह जिलों के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसमें आलीराजपुर, सिंगरौली, उमरिया, बैतूल, मंडला और अनूपपुर जिले शामिल हैं।

श्री शाह ने बताया कि आलीराजपुर में महुआ फूल और सफेद मूसली की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने से विशेष प्रयास कर विपणन और प्र-संस्करण के लिए दो वन धन केंद्र में मशीन स्थापित की जाएंगी। सिंगरौली जिले में महुआ फूल के प्र-संस्करण में सात वन धन केंद्रों का उपयोग किया जाएगा। उमरिया जिला में महुआ फूलों के प्र-संस्करण एवं विपणन के लिए स्थापित छह वन धन केंद्र के जरिए महुआ लड्डू, बिस्किट और केक बनाने के साथ महुआ बीज से तेल निकालने की योजना तैयार की गई है। स्थानीय वृक्षारोपण योजना में छह स्थानों पर महुआ के पौधों का रोपण भी कराया गया है। वन मंत्री ने बताया कि बैतूल जिले में महुआ फूल और अचार गुठली के प्र-संस्करण एवं विपणन के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तरह किसानों को भी निजी भूमि पर औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कराया जाएगा। इन केंद्रों पर तैयार उत्पाद स्थानीय बाजार, ट्राइफेड और संजीवनी केंद्रों के माध्यम से विक्रय कराया जाएगा। श्री शाह ने बताया कि मंडला जिले में आंवला, अर्जुन छाल, शहद और महुआ के प्र-संस्करण की योजना तैयार की गई है। अनूपपुर जिले में गुलबकावली के संरक्षण एवं उत्पादन के लिए एक्शन प्लान के तहत पौधा-रोपण सहित विशेष प्रयास किए जाएंगे।

एक जिला-एक उत्पाद योजना

पार्टी संगठन के विचार को सर्वव्यापी बनाएं : शर्मा

भोपाल (एजेंसी)। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की एक दिवसीय बैठक बुधवार को राजगढ़ के संस्कृति पैलेस में आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने संगठन का विस्तार कर इसे सुदृढ़ और सर्वव्यापी बनाने के साथ ही टैक्नोलॉजी का उपयोग करने की बात पर जोर दिया।

राजगढ़ में हुई भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की एक दिवसीय बैठक

प्रथम सत्र में अपने उद्बोधन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। इस संगठन को पं दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता, स्व. प्यारेलाल खण्डेलवाल, सकलेचा जी, पटवा जी और स्व कैलाश जोशी जैसे लोगों ने सींचा है। संगठन का और विस्तार करते हुए इसे सक्षम और सुदृढ़ बनाकर सर्वव्यापी बनाने की बात करते हुए कहा कि हमारा संगठनात्मक ढांचा ही हमारी ताकत है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम संगठन के विचार को अपने कार्य और व्यवहार से आमजन के बीच ले जाएं और उसे सर्वव्यापी बनाएं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। हमें उन चुनौतियों का सामना करते हुए समाज को तोड़ने वाले लोगों को अपने काम के माध्यम से जवाब देना है।

प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे और संगठन एक दूसरे के पर्याय थे। संगठन को गढ़ना उनके मूल में था। इसलिए ठाकरे जी ने संगठन को गढ़ते हुए जो.जो काम किए हैं उन्हें हमें अक्षुण्ण रखना है। सबको साथ लेकर चलना है और सबके साथ चलना है।

सरकार और संगठन एकजुट होकर काम करें : शिवराज सिंह

बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा मंत्र सामाजिक समरसता का है। हमारा हर काम समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़कर होता है। लेकिन हमारे विचार विरोधी लोग और प्रतिद्वंद्वी तिल का ताड़ बनाने का काम कर रहे हैं। अब समय है कि सरकार और संगठन एकमेव होकर और अधिक ताकत के साथ काम करें। केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएं।

संगठन की सफलता के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाएं : मुरलीधर राव

समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसा संगठन है, जो अपने कार्यकर्ताओं को समय-समय पर प्रशिक्षित करता है। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का युग है। इसलिए संगठन की सफलता के लिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। मुरलीधर ने अधिकतम प्रवास करने सलाह दी। बैठक का समापन राष्ट्रगान जन-गण-मन के साथ हुआ। इस अवसर पर पार्टी के समस्त प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे। संचालन प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने एवं आभार प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह ने व्यक्त किया।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर किया अनुरोध

पीएम आवास योजना के तहत 639.47 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएं

अमृत योजना के 130 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 104 करोड़ भी उपलब्ध कराने को कहा

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन की कुल राशि 873.47 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही भोपाल और ग्वालियर शहर वाटर प्लस के प्रमाणन हेतु पुनः सत्यापन अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सौंपे पत्र में अनुरोध किया है कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त की कुल राशि रुपए 639.47 करोड़, अमृत योजना के अंतर्गत केंद्रांश की शेष राशि रुपए 130 करोड़ एवं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी-एक) के अंतर्गत केंद्रांश की शेष राशि 104 करोड़ शीघ्र उपलब्ध कराएं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री पुरी को सौंपे पत्र में लिखा है कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद कठिन परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरों में उल्लेखनीय विकास करने के लिए मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में मध्यप्रदेश आज देश में अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी-2) की घोषणा के लिए भी मैं मध्यप्रदेश शासन की ओर से आपका आभारी हूं। दोनों ही योजनाएं देश के शहरों में स्वछ जल, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में अत्याधिक महत्वपूर्ण साबित होंगी।

बताईं प्रदेश की उपलब्धियां

पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश देश के द्वितीय स्थान पर है तथा पीएम स्वनिधि के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कान्टेस्ट 2020 में राज्य को देश में द्वितीय स्थान का गौरव प्राप्त हुआ तथा मध्यप्रदेश के 5 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में कुल 11 अवार्ड प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के द्वारा 8 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृत कर, 4 लाख से अधिक आवासों का निर्माण अल्प समय में पूरा किया है, आज इस योजना में हम देश में द्वितीय स्थान पर हैं। अमृत योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 199 परियोजनाओं में से 135 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा शेष 64 परियोजनाओं में से 57 परियोजनाएं भी मार्च 2022 तक पूर्ण कर ली जायेंगी। केवल 7 परियोजनाओं को पूरा करने में मार्च 2023 तक का समय लगेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्यप्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता को एक अभियान के रूप में आत्मसात किया है। इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश का इंदौर वाटर प्लस शहर बना है, और प्रदेश के 293 शहर ओडीएफ प्लस प्लस घोषित हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिदृश्य में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में होगा।

राव और शर्मा आज करेंगे साइबर योद्धाओं से संवाद

भोपाल । भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा गुरुवार, 9 सितंबर को भोपाल में साइबर योद्धाओं से संवाद करेंगे। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री राव एवं श्री शर्मा गुरुवार दोपहर साढ़े तीन बजे समन्वय भवन, एपेक्स बैंक, न्यू मार्केट, भोपाल में साइबर योद्धाओं के साथ 'कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय एवं भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां' विषय पर संवाद करेंगे।

जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंदजी के जन्मोत्सव में शामिल होंगी अर्चना

भोपाल, (रासं)। जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपनंदजी सरस्वती महाराज के गोटेगांव में आयोजित होने वाले जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल नौ सितंबर को शुभकामनाएं प्रेषित करने हेतु प्रस्थान करेंगी। साथ ही प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों,बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपने संघर्ष को पूरी ताकत से लड़ने हेतु (ज्योतेश्वर आश्रम) गोटेगांव नरसिंहपुर में शंकराचार्य जी से आर्शिवाद प्राप्त करेंगी।

विजयवर्गीय ने अरविंद मेनन को दी बधाई

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन विवाह के बाद बुधवार को इंदौर में सपत्नीक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से भेंट करने पहुंचे। राजनीति से अलग ये एक सुखद प्रसंग रहा। मेनन जी और उनकी पत्नी को सफल पारिवारिक जीवन के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने बधाई दी।

महिला कांग्रेस की संभाग एवं प्रकोष्ठ के प्रभारियों के नामों की घोषणा

भोपाल । मप्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सागर एवं शहडोल संभाग की बैठक ली। इस बैठक में सागर संभाग से आई महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने श्रीमती जायसवाल को संभाग की स्थितियों से अवगत करवाया।

डॉ. जायसवाल ने ली सागर और शहडोल संभाग की बैठक

बैठक में आगामी दिनों मे होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा की और कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया। बैठक में अभा महिला कांग्रेस द्वारा 15 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में पहुचने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में श्रीमती जायसवाल ने प्रदेश के समस्त संभागों की प्रभारियों एवं अन्य प्रकोष्ठो के प्रभारियों के नामों की घोषणा भी की। जिसमें भोपाल संभाग प्रतिभा विक्टर, सागर संभाग करुणा शर्मा, इंदौर संभाग से पुष्पा शर्मा एवं नीरू शर्मा, ग्वालियर चम्बल सीमा समाधिया, उज्जैन संभाग अदिति दवेसर, जबलपुर संभाग मनीषा किशोर राय, ग्वालियर एवं नर्मदापुरम संभाग प्रतिभा तोमर, रीवा संभाग गीता शरद तिवारी, शहडोल संभाग अनुभा शर्मा। वहीं श्रीमती जायसवाल ने प्रदेश आईटी एवं सोशल मीडिया सेल करुणा शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता अंजु सिंह बघेल, अदिति दवेसर, प्रदेश कार्यालय प्रभारी प्रतिभा विक्टर, प्रदेश महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ अदिति दवेसर एवं प्रतिभा तोमर, प्रदेश एनजीओ प्रकोष्ठ पुष्पा शर्मा एवं अंजना चतुर्वेदी तथा प्रदेश लीगल प्रकोष्ठ विनीता पाठक को प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया है। श्रीमती जायसवाल महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों के साथ विधायक एवं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा द्वारा आयोजित जन आक्रोश पदयात्रा में भी शामिल हुईं।

योगी सरकार में ये मुमकिन नहीं : जयभान सिंह पवैया

भोपाल (एजेंसी)। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नमाज के लिए अलग जगह की मांग पर कहा कि यह बिना सिर पैर की मांग उठ रही है जो बहुत मूर्खतापूर्ण है। यह देश को तोड़ने वाली मांगें हैं। अगर एक कक्ष इस्लामिक उपासना के लिए दे दिया जाए किसी विधानसभा में। तो मेरे तो कम से कम 100 देवता ऐसे हैं जिनकी मैं पूजा करता हूं। एक स्थान हनुमान जी के लिए चाहिए ,एक नारायण भगवान के लिए चाहिए, एक शंकर भगवान का चाहिए ,गणपति का चाहिए और कार्तिकेय भगवान का चाहिए।

मामला यूपी विधानसभा में नमाज के लिए अलग जगह देने का

श्री पवैया ने कहा कि अगर विधानसभा में एक कक्ष मांग रहे हैं तो ऐसा करें विधानसभा के बराबर कोई बड़ी मस्जिद हो उसे विधानसभा के लिए दे दें, हम अपना काम वहां कर लेंगे और विधानसभा को मस्जिद बना दें।

यह किस तरह की मांग है, इस देश इसी तरह का तमाशा होता रहा है। उत्तर प्रदेश में किस तरह का तमाशा करने की कोशिश केवल पोलराइजेशन करने की कोशिश। योगी सरकार में यह मुमकिन नहीं है। प्रजातंत्र के मंदिर को उपासना के नाम पर झगड़े का केंद्र बनाना यह कमजोर करता है देश को।

विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने की नागपुर में मध्यप्रदेश भवन के स्थापना की पहल

भोपाल (एजेंसी)। मप्र विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नागपुर (महाराष्ट्र) में मध्यप्रदेश भवन की स्थापना की पहल की है। यह भवन मध्यप्रदेश और विशेषकर विंध्य अंचल से इलाज के लिए नागपुर पहुंचने वाले लोगों के ठहरने के लिए एक सर्वसुविधा युक्त भवन होगा।

सामाजिक संस्था ने किया स्वागत

श्री गौतम का नागपुर में मध्य भारत विकास संघ द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर नागपुर में रहने वाले विंध्य अंचल के कई प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। श्री गौतम अपने नागपुर प्रवास के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों के कार्यालय भी पहुंचे और वहां संपादकीय टीम के साथ समसामयिक विषय पर संवाद किया।

श्री गौतम ने बुधवार को नागपुर में मध्य भारत विकास संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में इस भवन के निर्माण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। श्री गौतम ने कहा कि विंध्य अंचल से हजारों लोग नागपुर में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। रीवा से ही कई बसें भरकर मरीज और उनके परिजन नागपुर में हर सप्ताह आते हैं। अस्वस्थता के कारण ये लोग पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे होते हैं, उस पर नागपुर में रहने-ठहरने में होने वाला खर्च इनकी कमर तोड़ देता है। श्री गौतम ने कहा कि उनके मन में बहुत पहले से यह विचार था कि दिल्ली की तर्ज पर नागपुर में भी मध्यप्रदेश भवन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला प्रयास तो यह होना चाहिए कि सरकार के स्तर पर यह भवन बने, यदि यह मुश्किल है तो फिर कोई ट्रस्ट बनाकर भी यह कार्य किया जा सकता है। श्री गौतम ने कहा कि इस कार्य के लिए अपने स्तर पर पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

आवासीय विद्यालयों में हो शत-प्रतिशत सीटों पर प्रवेश

भोपाल (एजेंसी)। जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में संचालित आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध सीटों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की।

जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह बुधवार को मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकडेमिक सोसायटी की बैठक को संबोधित कर रहीं थी। बैठक में बताया गया कि सोसायटी द्वारा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 155 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, आयुक्त जनजातीय कार्य संजीव सिंह, संचालक सुश्री शैलबाला मार्टिन एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में मंत्री सुश्री सिंह ने कहा कि आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश में वर्तमान में 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में करीब 25 हजार जनजातीय छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में नेशलन टेस्टिंग एजेन्सी से रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

वन अधिकार पट्टों के पुनः परीक्षण के कार्य में तेजी लाएं

मंत्री सुश्री मीना सिंह ने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों को पूर्व के निरस्त दावों के पुनः परीक्षण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये है। बैठक में बताया गया है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा अब तक प्रदेश में 34 हजार 152 दावे मान्य किएजा चुके हैं। बैठक में वन अधिकार दावों के निराकरण के लिए तैयार किए गए एमपी वन मित्र पोर्टल पर भी चर्चा की गई। यह पोर्टल महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) ने तैयार किया है। पोर्टल को श्रेष्ठ कार्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाने के लिए इस वर्ष नामांकित किया गया है।

अदरक के क्षेत्र में बड़वानी करेगा नए कीर्तिमान स्थापित : कुशवाह

प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री ने ऑनलाइन वेबिनार को किया संबोधित

भोपाल (एजेंसी)। आत्म-निर्भर मप्र अभियान के तहत बुधवार को बड़वानी में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन पर किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने भी किसानों को आनलाइन वेबीनार के माध्यम से संबोधित किया। विभिन्न उद्यानिकी विशेषज्ञों ने वर्चुअल तरीके से उपस्थित किसानों को आय दोगुनी करने के लिए उन्नत तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

किसानों के प्रश्नों-जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यशाला में एक जिला-एक उत्पाद में चयनित अदरक उत्पादन के लिए किए जाने वाले प्रयासों एवं विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मिलने वाले अनुदानों के बारे में विस्तार से बताया। बड़वानी के जलसा रिसोर्ट में आयोजित संगोष्ठी को वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि राज्य शासन का प्रयास है कि किसानों की आय दोगुनी हो। इसके लिए एक जिला-एक उत्पाद में स्थानीय स्तर पर उत्पादित फसलों को बढ़ावा देने एवं उससे संबंधित प्रोसेस यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है। बड़वानी जिले के लिए अदरक का चयन किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित वेबिनार कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अदरक के क्षेत्र में बड़वानी जिला नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। वेबिनार में ग्लोबल फूड के सीईओ रामनाथ सूर्यवंशी ने भी किसानों को प्रोत्साहित किया।

शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म में नजर आएंगी प्रियामणि

शाहरुख खान और नयनतारा की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग शनिवार से पुणे में शुरु हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस प्रियामणि भी नजर आएंगी। जिन्हें आखिरी बार द फैमिली मैन में देखा गया था।

प्रियामणि फिल्म की कहानी में मुख्य किरदार निभाती दिखाई देंगी। प्रियामणि फिल्म के पुणे शेड्यूल में शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शामिल होंगी। प्रियामणि पहले से ही पुणे पहुंच चुकी हैं। फिल्म के नाम का अब तक खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्शन से भरपूर इस फिल्म पर टीम अपना काम शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म के करीबी सूत्र ने बताया कि फिल्म में सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी मुख्य भूमिका में हैं। दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख और प्रियामणि ने चेन्नई एक्सप्रेस में पहली बार साथ काम किया था। हालांकि, इस फिल्म में प्रियामणि एक गेस्ट की भूमिका निभा रही हैं। एटली डायरेक्टोरियल का निर्माण शाहरुख खान के बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा किया जा रहा है। इस फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में नजर आएंगे।

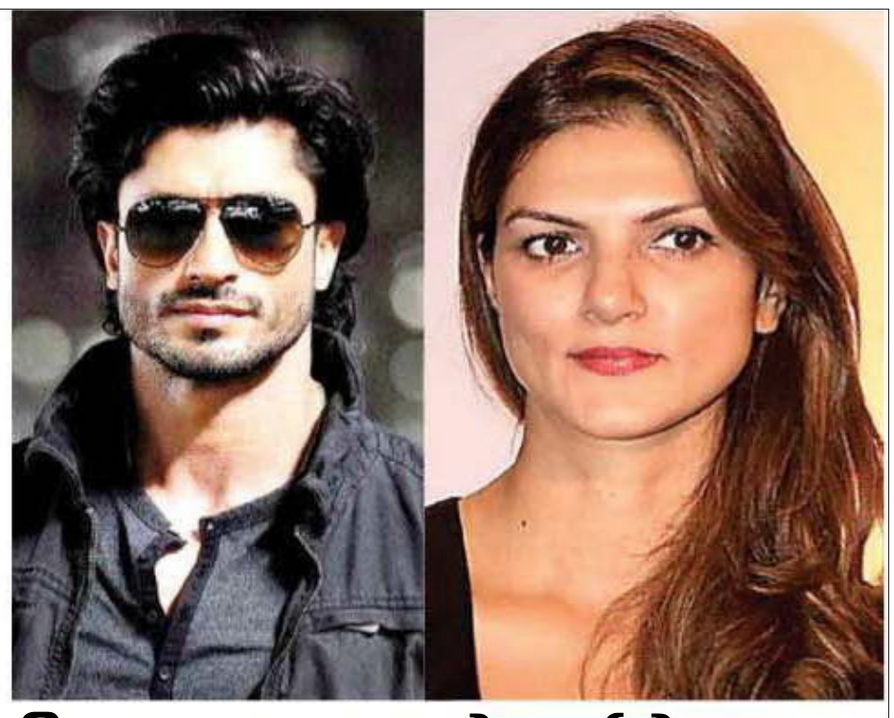

विद्युत जामवाल ने गर्लफ्रेंड संग गुपचुप तरीके से की सगाई

अभिनेता विद्युत जामवाल और फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी के गुपचुप तरीके से सगाई कर लेने की चर्चाएं हैं। दोनों की साथ की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वे ताजमहल के सामने खड़े होकर पोज दे रहे हैं। विद्युत और नंदिता हाथों में हाथ डाले हुए हैं। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसी बीच नेहा धूपिया के पोस्ट ने हलचलें बढ़ा दीं।

-सगाई की चर्चा

'कमांडो' फेम विद्युत जामवाल पहली बार सार्वजनिक

नेहा धूपिया के इस पोस्ट ने किया कंफर्म!

रूप से नंदिता के साथ दिखे हैं। तस्वीरों में नंदिता की रिंग ने भी सबका ध्यान खींचा। दोनों ने प्यार के प्रतीक ताजमहल के सामने जिस तरह खड़े होकर पैपराजी को फोटो दीं उसके बाद ही यह कहा जाने लगा कि उन्होंने सगाई कर ली है।

-नेहा धूपिया का पोस्ट

इसी बीच नेहा धूपिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर विद्युत और नंदिता की तस्वीर के साथ हार्ट का इमोजी पोस्ट किया और लिखा- 'सबसे अच्छी खबर। बधाई विद्युत जामवाल और नंदिता महतानी।' नेहा धूपिया के इस पोस्ट के बाद यह कंफर्म माना जा रहा है कि उन्होंने सगाई कर ली है हालांकि अभी तक कपल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

जासूस के किरदार में नजर आएंगे दिलजीत दोसांझ

सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के प्रशंसकों के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है। दिलजीत जल्द ही फिल्ममेकर अली अब्बास जफर की अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में दिलजीत जासूस शेरदिल का किरदार प्ले करते दिखाई देंगे। खबरों की मानें तो यह एक क्राइम कॉमेडी फिल्म होगी। जिसमें दिलजीत के अलावा सुमित व्यास, बोमन ईरानी और बनिता संधू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का टाइटल डिटेक्टिव शेरदिल रखा गया है। फिल्म में दिलजीत एक इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में दिखाई देंगे। अली अब्बास ने खुद फिल्म की पटकथा लिखी है। डिटेक्टिव शेरदिल एक शौकिया जासूस की कहानी है। इस थ्रिलर कॉमेडी फिल्म की पृष्ठभूमि क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है। बनिता फिल्म में दिलजीत के अपोजिट नजर आएंगी। बोमन और सुमित के किरदारों से जुड़ी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अली अब्बास के सहयोगी रहे रवि छाबड़िया इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग बुडापेस्ट में शुरू हो चुकी है। अगले महीने तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी।

RSS और तालिबान की तुलना कर घिरे जावेद अख्तर

गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर अपने हालिया बयान को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं.बीजेपी नेता राम कदम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक वह आरएसएस की तुलना तालिबान से करने वाले अपने हालिया बयानों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी फिल्में देश में नहीं दिखाई जाएंगी. गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर अपने हालिया बयान को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. बीजेपी नेता राम कदम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक वह आरएसएस की तुलना तालिबान से करने वाले अपने हालिया बयानों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी फिल्में देश में नहीं दिखाई जाएंगी. एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि, तालिबान बर्बर हैं, उनकी हरकतें निंदनीय हैं, लेकिन आरएसएस, विहिप और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं. जावेद अख्तर का यह बयान बीजेपी की युवा शाखा को पसंद नहीं आया और उन्होंने जावेद अख्तर के जुहू स्थित घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. बीजेपी ने कहा कि, अगर आरएसएस तालिबान की तरह होता, तो उन्हें इस तरह के बयान देने की अनुमति नहीं दी जाती. भाजपा विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा, आरएसएस से जुड़े राजनेता सरकार में मामलों के शीर्ष पर हैं. राज धर्म का पालन करते हुए ये लोग देश चला रहे हैं, अगर वे तालिबान की तरह होते तो क्या जावेद अख्तर को ऐसा बयान देने की अनुमति होती. लेकिन इस तरह की टिप्पणी करके उन्होंने देश में गरीब लोगों का काम करने वाले आरएसएस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हम उनकी फिल्मों को इस देश में नहीं चलने देंगे. वहीं, भाजपा की युवा शाखा ने शनिवार को जावेद अख्तर के जुहू स्थित आवास तक विरोध मार्च निकाला, जिसमें उनके बयान के लिए माफी की मांग की गई. उन्होंने कहा, हमें लगता है कि अख्तर मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं. इस देश ने उन्हें सब कुछ दिया है. आरएसएस जमीनी स्तर पर लोगों की मदद करता है और उसने उनकी तुलना तालिबान से की है. यह अस्वीकार्य है. अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ हमारा आंदोलन और तेज हो जाएगा.

ऊंचाई में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा

अमिताभ बच्चन इन दिनों डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई को लेकर चर्चा में रहे हैं। फिल्म में अमिताभ मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऊंचाई में परिणीति चोपड़ा की भी एंट्री हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म में मेकर्स ने अमिताभ के अपोजिट परिणीति को कास्ट कर लिया है। फिल्म में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते नजर आएंगी। अमिताभ-परिणीति के अलावा इस फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता और बोमन ईरानी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। अनुपम, बोमन और अमिताभ तीन पुराने दोस्तों की भूमिका में दिखाई देंगे। परिणीति और नीना के किरदार के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। इस फिल्म की कहानी सूरज ने खुद लिखी है। फिल्म की शूटिंग नेपाल के खूबसूरत लोकेशंस में होगी। खबरों के मुताबिक, राजश्री प्रोडक्शंस वेंचर 5 अक्टूबर को काठमांडू घाटी में इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली है। काठमांडू और उसके आसपास एक महीने के शेड्यूल की योजना बनाई गई है।

सैफ ने भूत पुलिस में अपने किरदार के बारे में की बात

अभिनेता सैफ अली खान ने आगामी हॉरर-कॉमेडी भूत पुलिस और उनके चरित्र विभूति के बारे में बात की है। फिल्म दो भाइयों विभूति और चिरौंजी पर केंद्रित है क्योंकि वे देश भर में अपनी वैन में यात्रा करते हैं और भूत, जिन्न, डायन, चुरैल और कई अन्य लोगों का शिकार करते हैं। सैफ ने साझा किया कि वह फिल्म में विभूति का किरदार निभाने के लिए वह क्यों सहमत हुए। उन्होंने कहा, पहली बार जब मैंने इसे सुना तो मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई, यह सबसे आश्चर्यजनक मनोरंजक स्क्रिप्ट में से एक थी और वह (विभूति के चरित्र) के कारण बहुत दिलचस्प चरित्र था। सैफ ने कहा मुझे उसके कपड़े पहनने का तरीका पसंद आया, वह जिस दुनिया से है, जिस लहजे में वह बोलता है। यह एक दिलचस्प चरित्र है। भूत पुलिस में जैकलीन फर्नांडीज, यामी गौतम, जावेद जाफरी और जेमी लीवर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

टाइगर 3 की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे सलमान और कैटरीना

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ जल्द ही अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी टाइगर की अगली फिल्म टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं। सलमान और कैटरीना इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग तुर्की में कर रहे हैं। फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के बीच सलमान खान, कैटरीना कैफ और फिल्म की टीम ने तुर्की के संस्कृति और पर्यटन मंत्री मेहमत नूरी इरसॉय से मुलाकात की है। जिसकी तस्वीर को सलमान और कटरीना ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तुर्की के मंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खास मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हमारी मुलाकात बॉलीवुड के मशहूर कलाकार सलमान खान और कैटरीना कैफ से हुई, जो अभी हमारे देश में अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए हैं। तुर्की इसी तरह इंटरनेशनल सिनेमा प्रोजेक्ट्स की मेजबानी करता रहेगा।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग : शार्दुल ठाकुर और क्रिस वोक्स लगाई छलांग

दुबई (एजेंसी)।

भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने बुधवार को आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में छलांग लगाई। इसके अलावा भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी अपने रैंकिंग में इजाफा किया।

शार्दुल ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की दोनों पारियों में 57 और 60 रनों की शानदार पारी खेली जिसके चलते वह बल्लेबाजों की सूची में 79वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वोक्स जिन्होंने करीब एक साल बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी की है, उन्होंने चौथे टेस्ट की दोनों पारियों में 50 और 18 रन की पारी खेली जिससे वह बल्लेबाजों के रैंकिंग में सात पायदान की उछाल के साथ 87वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने द ओवल में सात विकेट भी अपने नाम किए थे जिसके कारण उन्होंने गेंदबाजों की रैंकिंग में तीन पायदान का इजाफा किया और वह 23वें स्थान पर पहुंच गए। वोक्स ने ऑलराउंडरों की रैंकिंग में वापसी करते हुए दो स्थान का इजाफा किया और सातवें स्थान पर पहुंच गए। भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह ने द ओवल में चार विकेट अपने नाम किए थे। अब सीरीज में उनके कुल 18 विकेट हो गए हैं। बुमराह ने एक स्थान का इजाफा किया है और अब वह 10वें स्थान से नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिंसन जिनके नाम सीरीज में 21 विकेट है, उन्होंने भी गेंदबाजों की सूची में तीन स्थान का इजाफा किया है अब वह 33वें स्थान पर आ गए हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बल्लेबाजों की सूची में 813 रेटिंग अंक के साथ पांचवें नंबर पर बने हुए। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप रैंकिंग में नौ स्थान ऊपर आ गए हैं। अब वह बल्लेबाजों की सूची में 49वें स्थान पर हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज के पहले चार मैच नहीं खेलने के बावजूद रविचंद्रन अश्विन् गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं।

यूएस ओपन : अलकार्ज के रिटायर होने के कारण सेमीफाइनल में पहुंचें एलियासिमे

न्यूयॉर्क (एजेंसी)।

कनाडा के फेलिक्स एउगर एलियासिमे स्पेन के कार्लोस अलकार्ज के चोटिल होने की वजह से रिटायर होने के कारण यहां जारी यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। एलियासिमे ने पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया था और वह दूसरे सेट में भी 3-1 से आगे चल रहे थे। लेकिन तभी अलकार्ज ने मैच से हटने का फैसला लिया और एलियासिमे पहली बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। 21 वर्षीय एलियासिमे कनाडा के पहले टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। एलियासिमे ने एटीपीटूर डॉट कॉम से कहा, यह एक अद्भुत मील का पत्थर है। यह मेरे लिए शानदार टूर्नामेंट रहा है। हालांकि, मैच का अंत अजीब था। मेरे पास शुक्रवार को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के खिलाफ खेलने का मौका होगा। मेरे पास मेरे पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में जाने का मौका होगा। यह आश्चर्यजनक है, मैं खुश हूं कि मैं सफल हूं और मैं अगला मैच जीतने की कोशिश करूंगा। 12वीं सीड का मुकाबला दूसरी सीड और दो बार फाइनल में पहुंचने वाले रूस के डेनिल मेदवेदेव से मुकाबला होगा।

तालिबान ने कहा, अफगानिस्तान में महिलाओं को क्रिकेट सहित कोई खेल खेलने की इजाजत नहीं

काबुल। तालिबान ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को क्रिकेट सहित कोई खेल खेलने की अनुमति नहीं है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच इस साल नवंबर में होबार्ट में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच पर संशय के बादल छा गए हैं। तालिबान कलचरल कमिशन के डिप्टी हेड अहमदुल्लाह वासिक ने एसबीएस न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत होगी क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि महिलाएं क्रिकेट खेलें। क्रिकेट में उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां उनका चेहरा और शरीर ढका नहीं होगा। इस्लाम औरतों को इस तरह देखने की इजाजत नहीं देता। यह मीडिया का जमाना है, और इसमें फोटो और वीडियो होंगे और फिर लोग इसे देखेंगे। इस्लाम और इस्लामिक अमीरात महिलाओं को क्रिकेट खेलने या उस तरह के खेल खेलने की इजाजत नहीं देते। नवंबर 2020 में, 25 महिला क्रिकेटरों को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) द्वारा केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया था। काबुल में 40 महिला क्रिकेटरों के लिए 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के सभी 12 पूर्ण सदस्यों की राष्ट्रीय महिला टीम होना जरूरी है और आईसीसी केवल पूर्ण सदस्यों को ही टेस्ट मैच खेलने की अनुमति है। यह पूछे जाने पर कि महिला क्रिकेट नहीं होने का मतलब आईसीसी होबार्ट टेस्ट को रद्द कर सकता है। इस पर वासिक ने कहा कि तालिबान समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, इसके लिए अगर हमें चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा तो हमने अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है ताकि इस्लाम का पालन किया जा सके। हम इस्लामी मूल्यों को पार नहीं करेंगे, भले ही इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हो। हम अपने इस्लामी नियमों को नहीं छोड़ेंगे। वासिक ने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को खरीदारी जैसे जरूरतों के आधार पर बाहर जाने की इजाजत दी है और खेल को जरूरी नहीं माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डैन तेहान ने तालिबान द्वारा महिला एथलीटों को खेल खेलने से प्रतिबंधित करने के फैसले को अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक बताया।

एशियाई युवा खेल दिसंबर 2022 तक स्थगित

गुआंग्झोउ। कोरोना वायरस के कारण एशियाई युवा खेल 2021 को दिसंबर 2022 तक स्थगित किया गया है। चीन ओलंपिक समिति (सीओसी) ने बुधवार को इसकी घोषणा की। तीसरे एशियाई युवा खेल का आयोजन दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत के शांतोउ में 20 से 28 नवंबर तक होना था। सीओसी के बयान के अनुसार, नया कार्यक्रम 20 से 28 दिसंबर 2022 तक तय किया गया है। बयान में कहा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए), सीओसी और स्थानीय आयोजन समिति ने गहन चर्चा की और प्रत्येक राष्ट्रीय/क्षेत्रीय ओलंपिक समिति के हितों की रक्षा करने और सभी एथलीटों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए एक साथ निर्णय लिया।

इंग्लैंड अगले साल जूलाई में भारत से खेलेगा टी20 और वनडे सीरीज

लंदन (एजेंसी)।

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि इंग्लैंड की पुरुष टीम विश्व चैंपियन न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ 2022 की घरेलू क्रिकेट की शुरूआत करेगी, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज भी शामिल है।

जोए रूट की अगुआई में टेस्ट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो जून से लॉर्डस में सीरीज की शुरुआत करेगी बाद में ट्रेंट ब्रिज (10-14 जून) और एमराल्ड हेडिंग्ले (23-27 जून) में बाकी के दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ईसीबी ने कहा भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज एक जुलाई से ओल्ड ट्रेफोर्ड में शुरु होगी उसके बाद ट्रेंट ब्रिज (3 जुलाई) और एजेस बाउल (6 जुलाई) में बाकी के दौ मैच खेले जाएंगे। तीन मैचों की रॉयल लंदन सीरीज एजबस्टन में नौ जुलाई से शुरू होगी फिर किआ ओवल (12 जुलाई) और लॉर्डस (14 जुलाई) में बाकी के दौ मैच खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के दौरे की शुरूआत तीन मैचों की रॉयल लंदन सीरीज से होगी। सीरीज का पहला मैच एमिरेट्स रिवरसाइड (19 जुलाई) में खेला जाएगा जबकि एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड (22 जुलाई) और एमराल्ड हेडिंग्ले (24 जुलाई) में शेष दो मैच कराए जाएंगे। ईसीबी ने कहा, इंग्लैंड फिर दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिस्टल (27 जुलाई), सोफिया गार्डन (28 जुलाई) और एजेस बाउल (31 जुलाई) में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज लॉर्डस (17-21 अगस्त) से शुरु होगी बाद में एजबेस्टन (अगस्त 25-29) और किआ ओवल (8-12 सितंबर) में सीरीज के बाकी टेस्ट मैच खेले जाएंगे।

जब मैं खराब स्थिति में था तो राजस्थान रॉयल्स ने मेरी मदद की : करियप्पा

दुबई। लेग स्पिनर केसी करियप्पा का कहना है कि जब वह खराब स्थिति में थे तो राजस्थान रॉयल्स ने उनकी काफी मदद की। करियप्पा और ऑलराउंडर श्रेयस गोपाल ने हाल के महीनों में ज्यादा परिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन यह दोनों राजस्थान रॉयल्स को यूएई में होने वाले आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के दौरान प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। करियप्पा ने कहा, जब मैं कर्नाटक टीम में नहीं चुना गया तो मैं काफी निराश हो गया था। मैंने पिछले साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बेहतर किया लेकिन इसके बाद चीजें मेरे लिए सही नहीं रही। उन्होंने कहा, जुबिन भरुचा सर ने मुझे बुलाया और आईपीएल ट्रॉयल्स देने के लिए कहा। मैं आश्चर्यचकित था कि एक साल से दूर रहने के बाद मुझे ट्रॉयल्स के लिए बुलाया गया है। हालांकि, मैं वहां गया और मैंने गेंदबाजी की। करियप्पा ने कहा, जुबिन सर ने फिर मुझे फोन किया और कहा, मैं 2015 से आपको देख रहा हूं, लेकिन आपको क्या दिक्कत है? आपकी फिटनेस को क्या हुआ है? हमें आपकी गेंदबाजी पसंद है लेकिन आपको अपनी फिटनेस ठीक रखनी होगी। यही वह क्षण था जब मुझे फिर से प्रेरणा मिली और मैंने लय में वापस आने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। इसलिए मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं वास्तव में उनका और राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी का शुक्रगुजार हूं। मुझे लगता है कि मैं उनकी वजह से अपने पैरों पर वापस आ गया हूं और अब मैदान पर उस विश्वास को चुकाने का समय आ गया है।

लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे : अमित मिश्रा

दुबई (एजेंसी)।

दिल्ली कैपिटल्स के लेग स्पिनर अमित मिश्रा का कहना है कि टीम आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी। दिल्ली अपने दूसरे चरण का अभियान सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 22 सितंबर को होने वाले मुकाबले से करेगी। अमित ने कहा, हमने पिछले दो सीजन में अच्छा किया है और ऐसा टीम के संयुक्त प्रयास के चलते हुआ है। कोच, चयनकर्ता और खिलाड़ी सभी लोगों को पिछले कुछ वर्षो में दिल्ली कैपिटल्स के विकसित होने का श्रेय जाता है। उन्होंने कहा, हम आईपीएल 2021 के पहले चरण के लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और सीजन शुरू होने पर एक समय में एक ही मैच पर ध्यान देंगे। दिल्ली ने पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन किया और आठ में से छह मुकाबले जीते। हालांकि, अमित का मानना है कि सीजन के शुरू होने पर सभी टीमों को दोबारा शुरूआत करनी होगी। अमित ने कहा, हम अभी तालिका में शीर्ष पर हैं, लेकिन हमें नए सिरे से शुरूआत करनी होगी। हमें अपनी रणनीति फिर से बनानी होगी। मुझे लगता है कि अब हर टीम के पास अच्छा प्रदर्शन करने का समान मौका है क्योंकि हम सभी टूर्नामेंट को फिर से शुरू कर रहे हैं। हम आईपीएल 2021 का दूसरा चरण एक अलग देश में खेल रहे हैं, इसलिए हमें यहां यूएई की परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी।

एमएमए खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए : रितु फोगाट

नई दिल्ली। पहलवान से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) फाइटर बनीं रितु फोगाट ने मंगलवार को भारत सरकार से देश में एमएमए को बढ़ावा देने में मदद करने का आग्रह किया और यह भी सुझाव दिया कि इस खेल के खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना चाहिए। रितु ने आईएएनएस से कहा, हम भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूं। मैं बस जो नए खिलाड़ी इस खेल को अपना रहे हैं उनके लिए यह बात कह रही हूं। उन्होंने कहा, सरकार को इसे बढ़ावा देना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह अब जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। अर्जुन पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार भी इस खेल में मिलनी चाहए। भारत में अन्य खेलों की तरह एमएमए का एक उचित मान्यता प्राप्त महासंघ होना चाहिए। हमारे पास भारत में बहुत प्रतिभा है, जो खेल में शामिल होने के इच्छुक हैं। हमारे मुकाबलों का भी उचित प्रसारण होना चाहिए ताकि लोग इसे देख सकें। रितु ने सिंगापुर में एक चैंपियनशिप के एटॉमिक वेट ग्रां प्री के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने चीन की वर्ल्ड नंबर 2 मेंग बो को हराया, जो सात मैचों की अपराजित थी। 27 वर्षीय एमएमए फाइटर ने बड़ी जीत पर कहा, मेंग बो वास्तव में एक अच्छी खिलाड़ी हैं। वह नंबर 2 की दावेदार है। उसके पास मुझसे अधिक अनुभव है। लेकिन मैंने साबित कर दिया है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैंने इस मैच में कुछ कुश्ती चालों और एमएमए शैली के मिश्रण का इस्तेमाल किया। यह पूछे जाने पर कि क्या वह कुश्ती में वापसी करेंगी, रितु ने कहा, मैं कुश्ती में वापस आने के बारे में नहीं सोच रही हूं। मुझे पता है कि मेरे पिता चाहते हैं कि हम ओलंपिक पदक जीतें। संगीता विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेगी। उसने अच्छी वापसी की है। साथ ही, मेरी चचेरी बहन विनेश फोगाट भी कड़ी मेहनत कर रही हैं। वह इस बार टोक्यो ओलंपिक में बदकिस्मत रहीं, लेकिन उम्मीद है कि 2024 पेरिस में पदक जीतेंगी।

ओलंपिक कांस्य पदक पर बोले दिलप्रीत, यह भारतीय हॉकी के लिए नई शुरुआत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

युवा स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद भारतीय हॉकी टीम ने अपना मनोबल ऊंचा रखा और तोक्यो ओलंपिक में एतिहासिक कांस्य पदक नए युग की शुरुआत है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पिछले महीने तोक्यो खेलों में कांस्य पदक के साथ ओलंपिक पदक के 41 साल के इंतजार को खत्म किया। दिलप्रीत ने हॉकी इंडिया की विज्ञप्ति में कहा, ''हमने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की। हमने महामारी के कारण किसी मुश्किल को अपने मनोबल को प्रभावित नहीं करने दिया। सीनियर खिलाड़ियों ने लगातार हमारी हौसलाअफजाई की और हमें महसूस कराया कि हम यह कर सकते हैं।''

उन्होंने कहा, ''मेरा सचमुच में मानना है कि यह नई शुरुआत है। हम सभी और अधिक हासिल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमें और अधिक प्यार दें और हमारा समर्थन जारी रखें।'' दिलप्रीत ने कहा, ''और इसके लिए हमें लगता है कि हमें बड़े टूर्नामेंटों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं।'' भारतीय टीम के साथ 21 सालके दिलप्रीत ने अब तक शनदार प्रदर्शन किया है। वर्ष 2017 में जूनियर टीम के साथ सुल्तान आफ जोहोर कप में कांस्य पदक के दौरान अच्छे प्रदर्शन के बाद से दिलप्रीत के करियर ने नई बुलंदियों को छुआ है। उन्हें सीनियर शिविर के लिए बुलाया गया और 2018 से वह लगभग सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम का हिस्सा रहे जिसमें राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल के अलावा ओडिशा के भुवनेश्वर में विश्व कप भी शामिल है।

दिलप्रीत ने कहा, ''इस शानदार समूह का हिस्सा बनकर मैं भाग्यशाली महसूस करता हूं और हां, मेरा मानना है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत इतनी अच्छी रही।'' पंजाब के इस युवा फारवर्ड ने कहा कि 2018 एफआईएच पुरुष विश्व कप में भारत के क्वार्टर फाइनल में बाहर होने के बाद जब उन्हें टीम से बाहर किया गया तो उन्हें जो समर्थन मिला वह उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट रहा।